ग्रामीण उपभोक्ता

जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता

वर्ष-11, अंक-03, पृष्ठ-52, मार्च-2026, मूल्य-25 रुपए

संभावनाओं का दस्तावेज़!

दखल : हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खुलेगा कटेंट क्रिएटर्स के लिए स्कूलों में लैब

पहल : इनकम टैक्स में हेरफेर... घबराइये नहीं जेल नहीं जाएंगे...

राजपथ : हंगामा है क्यों बरपा, मी लॉर्ड...?

PROSPERITY THROUGH COOPERATION

NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA

विषयवस्तु

संपादकीय निदेशक
आशीष मिश्र
संपादक
बिनोद आशीष
समाचार संपादक
आरती झा
सहायक संपादक
अजय कुमार खुशबू
कॉपी डेस्क
सत्यम
विधिक सलाहकार
डी.के. दुबे

प्रशासनिक कार्यालय

101, शाहपुरी टॉवर, जनक सिनेमा कॉम्प्लेक्स के पीछे, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

संपर्क सूत्र

मो. नं.: +91-9899066717
graminupbhokta@gmail.com

प्रिंट लाइन

मुद्रक एवं प्रकाशक: प्रतिध्वनि मीडिया प्रा. लि. के लिए बिनोद आशीष द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित तथा पुरुराज प्रिंट एवं पैकेजिंग प्रा. लि. एल-19 सेक्टर-6 नोएडा (यूपी) 201301 से मुद्रित एवं ई-3 मिलाप नगर, नई दिल्ली-110058 से प्रकाशित

6 हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खुलेगा कटेंट क्रिएटर्स के लिए स्कूलों में लैब

13 राहत कम-वादा ज्यादा

19 इनकम टैक्स में हेरफेर... घबराइये नहीं जेल नहीं जाएंगे...

25 हंगामा है क्यों बरपा, मी लॉर्ड...?

35 आखिर, मैक्रां ने ऐसा क्या कहा जो भारत के बच्चों के लिए भी फिट बैठता है...?

40 किसानों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा बजट...?

ग्राहक प्रति

ग्रामीण उपभोक्ता

जागरूक उपभोक्ता | उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार की पहल | सुरक्षित उपभोक्ता

आप हासिल कर सकते हैं

हां, मैं ग्रामीण उपभोक्ता का ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं

टिक करें	अवधि	कुल अंक	मूल्य (रु.)	आपको देना है (रु.)
☐	1 वर्ष	12	300	250
☐	3 वर्ष	36	900	700
☐	5 वर्ष	60	1500	1200
☐	आजीवन (15 वर्ष)	180	4500	3500

अपनी पसंद के ऑफर पर निशान लगाएं और ग्राहकी फॉर्म भरकर इस पते पर भेजें: 101 शाहपुरी टॉवर, जनक सिनेमा कॉम्प्लेक्स के पीछे, जनकपुरी , नई दिल्ली-110058

चेक/डीडी से भुगतान

मैं ग्रामीण उपभोक्ता के पक्ष में भेज रहा हूं.................. दिनांक....................आहरित बैंक(बैंक का नाम).......................

चेक/डीडी नंबर.......................... दिल्ली से बाहर के चेक के लिए 50 रुपए अतिरिक्त दें। ऐट पार चेक के लिए लागू नहीं

नाम...पता...

शहर..राज्य..............................पिन...........................फोन नंबर (निवास)...............

मोबाइल नंबर.............................. ई-मेल...

आप ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका के बारे में अपनी राय हमें ऊपर दिए गए पते या फिर मेल पर भेज सकते हैं।
ई-मेल: graminupbhokta@gmail.com

ग्राहक प्रति

ग्रामीण उपभोक्ता

नाम...पता...

शहर..राज्य..............................पिन...........................फोन नंबर (निवास)...............

मोबाइल नंबर.............................. ई-मेल...

आप ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका के बारे में अपनी राय हमें ऊपर दिए गए पते या फिर मेल पर भेज सकते हैं।
ई-मेल: graminupbhokta@gmail.com

गलगोटिया के बहाने जॉम्बी युनिवर्सिटीज के यक्ष प्रश्न

सांसद मनोज झा ने पिछले दिनों शिक्षा की गुणवत्ता पर एक लेख में गलगोटिया के बहाने देश के विश्वविद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता के प्रश्नों को सामने रखा। उन्होंने ब्रिटिश लेखक पीटर फ्लेमिंग की किताब Academia : How Universities Die का जिक्र किया। इसमें संसाधन और गुणवत्ताविहीन विश्वविद्यालयों को जॉम्बी युनिवर्सिटीज़ कहा गया है। ऐसे विश्विवद्यालय भीतर से खोखले लेकिन बाहर से सक्रिय दिखने की कोशिश करते हैं। यक्ष प्रश्न गलगोटिया के बहाने ही सही, लेकिन क्या हमारे देश के विश्वविद्यालय जॉम्बी युनिवर्सिटीज़ ही तो नहीं बनते जा रहे हैं?

FEEDBACK
misraashish02@gmail.com
M.N. -9899152489

ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एआई (Artificial Intelligence) समिट को एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक आयोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। विश्वविद्यालय प्रशासन का उद्देश्य था कि देश-विदेश के विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों, स्टार्टअप संस्थापकों और विद्यार्थियों को एक मंच पर लाकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नवीनतम रुझानों और अवसरों पर चर्चा की जाए। लेकिन भारत मंडपम में हुई एआई इंपैक्ट समिट शायद उतनी अधिक चर्चा में नहीं रही जितना वहां पर एक स्टॉल लगाने वाली ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया युनिवर्सिटी। इस युनिवर्सिटी की ताकत इसी से समझ लीजिए कि समिट में स्टॉल लगाने के लिए जितनी जगह देश के चार प्रतिष्ठित आईआईटी को मिलाकर दी गई थी उससे ज्यादा अकेले इस युनिवर्सिटी को दी गई। युनिवर्सिटी का दावा था कि उसने अपने विश्वविद्यालय में एआईचालित रोबोट को विकसित किया है। कथित तौर उसकी इस अनोखी उपलब्धि का जिक्र देश के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स हैंडल पर भी किया था। मामला गरमाया, विवाद हुआ तो मंत्री जी ने भी अपने एक्स एकाउंट से रोबोट को गायब कर दिया। युनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से मामले को संभालने के लिए कई हथकंडे अपनाए लेकिन बात खराब हो चुकी थी। युनिवर्सिटी को वहां से अपना स्टॉल खाली करना पड़ा, जो बेइज्जती हुई वो अलग। गलगोटिया विश्वविद्यालय ने इस समिट को इंटरनेशनल एआई समिट के रूप में प्रचारित किया था। प्रचार सामग्री में दावे किए गए थे कि, इसमें वैश्विक स्तर के एआई विशेषज्ञों की भागीदारी हो रही है, उद्योग जगत की अग्रणी कंपनियों की उपस्थिति होगी, स्टार्टअप निवेश के अवसर मिलेंगे, छात्रों के लिए नेटवर्किंग और इंटर्नशिप संभावनाएं बनेंगी एवं साथ ही एआई आधारित नवाचार प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। सोशल मीडिया, वेबसाइट और पोस्टरों के माध्यम से इसे बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया। छात्रों और अभिभावकों के बीच यह धारणा बनी कि यह आयोजन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक साख को नई ऊंचाई देगा। समिट के दौरान और बाद में कुछ घटनाएं चर्चा का विषय बनीं। लेकिन असली बवाल हुआ एक रोबोट को लेकर। कहा गया कि युनिवर्सिटी ने दावा किया था कि वह उनके विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। लेकिन बाद में पता चला कि वह तो चीन का है। चीनी मीडिया तक भी यह खबर पहुंच गई और वहां इस समिट के साथ पूरे देश की खिल्ली उड़ी। एआई आधारित ट्रेंड एनालिसिस और हैशटैग कैंपेन ने "#AISummitControversy' जैसे टैग को ट्रेंड कराया। इससे विश्वविद्यालय की छवि पर प्रभाव पड़ा। जाहिर है, इसका असर छात्रों और अभिभावकों पर पड़ना ही था। छात्रों ने मांग की कि विश्वविद्यालय सवालों के जवाब दे।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि,कार्यक्रम में कुछ तकनीकी चुनौतियां थीं, जिन्हें स्वीकार किया गया। सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ वीडियो संदर्भ से काटकर दिखाए गए। प्रशासन ने दावा किया कि, रोबोट को लेकर कुछ गलतफहमियां थी। हमने कभी भी यह दावा नहीं किया कि उस रोबोट को उनकी युनिवर्सिटी ने तैयार किया है।

देश भर में सैकड़ों या हो सकता है उससे भी ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। सरकारी से ज्यादा निजी। इन सभी के बीच रैंकिंग, प्लेसमेंट और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को लेकर होड़ मची रहती है। इससे युनिवर्सिटी की ब्रांडिंग में भी मदद मिलती है।

लेकिन, कई युनिवर्सिटीज़ सरकारी वरदहस्त की आड़ में कुछ ऐसी हरकतें करने से नहीं चूकतीं जो उन्हें ही भारी पड़ जाती हैं। यही युनिवर्सिटी कुछ समय पहले भी चर्चा में आई थी जब एक राजनीतिक दल के विरोध में यहां के छात्रों के हाथ में प्लेकार्ड थमा दिया गया था। विरोध करने वाले छात्रों को यह तक नहीं पता था कि वे विरोध किस बात का कर रहे हैं। अरबन नक्सल की जगह एक छात्र उसे अरबन मैक्सवेल बोल रहा था। लाइमलाइट में आने के लिए भारत मंडपम में रोबोट का मसला भी कुछ अलग दिखने की कोशिश भर था।

सांसद मनोज झा ने पिछले दिनों शिक्षा की गुणवत्ता पर एक लेख में गलगोटिया के बहाने देश के विश्वविद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता के प्रश्नों को सामने रखा। उन्होंने ब्रिटिश लेखक पीटर फ्लेमिंग की किताब Academia : How Universities Die का जिक्र किया। इसमें संसाधन और गुणवत्ताविहीन विश्वविद्यालयों को जॉम्बी युनिवर्सिटीज़ कहा गया है। ऐसे विश्विवद्यालय भीतर से खोखले लेकिन बाहर से सक्रिय दिखने की कोशिश करते हैं।

यक्षप्रश्न गलगोटिया के बहाने ही सही, लेकिन क्या हमारे देश के विश्वविद्यालय जॉम्बी युनिवर्सिटीज़ ही तो नहीं बनते जा रहे हैं ?

आरती झा

हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खुलेगा कटेंट क्रिएटर्स के लिए स्कूलों में लैब

देश में बालिका शिक्षा, सशक्तिकरण एवं हैंडलूम क्षेत्र में विशेष रूप से दखल देते हुए उनके लिए नई योजनाओं एवं बजट आवंटन किया है। इन योजनाओं से सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सरकार की दखलों में देश के हर जिले में बालिका छात्रावास एवं लखपति दीदी की योजनाओं को और मजबूती देने के प्रस्ताव शामिल हैं।

देश में महिलाओं को समृद्ध एवं सशक्त करने के उद्देश्य से महिला साक्षरता पर विशेष जोर दिया गया है। वित्तमंत्री ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव रखा है। यानी आने वाले समय में बड़ी संख्या में नए हॉस्टल बनाए जाएंगे। इस कदम का मकसद लड़कियों की पढ़ाई को आसान और सुरक्षित बनाना है ताकि उन्हें स्कूल, कॉलेज या दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए रहने की दिक्कत न हो।

कंटेंट क्रिएटर्स की लैब

देश में 15000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर्स की लैब बनाई जाएगी। इसके लिए सरकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को सपोर्ट करेगी।

फार्मा उद्योग के लिए बड़ी योजनाएं

इसके अलावा वित्त मंत्री ने फार्मा इंडस्ट्री के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं। फार्मास्युटिकल एजूकेशन से संबंधित कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार ने देश में तीन नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर खोलने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ पहले से जो 7 संस्थान मौजूद हैं उन्हें और भी बेहतर बनाया जाएगा। फार्मा सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को मजबूत करने के लिए पूरे देश में 1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल ट्रायल सेंटर्स का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे मेडिकल और रिसर्च से जुड़े युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

प्रोफेशनल संस्थाओं जैसे आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई को भी सरकार ने इस बजट में सपोर्ट का ऐलान किया है। इन संस्थाओं में शॉर्ट टर्म और मॉड्यूलर कोर्स तैयार किए जाएंगे जिनमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और काम आने वाले टूल्स पर फोकस किया जाएगा। इससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में कॉर्पोरेट मित्रों की एक मजबूत टीम तैयार होगी। इससे इन शहरों में प्रोफेशनल्स सपोर्ट और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

> - **महात्मा गांधी हैंडलूम योजना के लिए और पैसा**
> - **पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर**

पर्यटन के क्षेत्र में दखल

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 20 पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइडों को तैनात करेगी। इसके लिए पहले ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों युवाओं को रोजागार मिलेगा और ट्रेनिंग सेंटर के जरिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

युनिवर्सिटी टाउनशिप

केंद्र सरकार बड़े इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स सेंटर्स

के आसपास पांच युनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने में मदद करेगी। इन टाउनशिप्स में कई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, छात्रों और स्टाफ के लिए रहने की सुविधा के साथ-साथ रिसर्च से जुड़ा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा। इसका मकसद, पढ़ाई, रिसर्च और इंडस्ट्री को एक ही जगह पर डेवलप करना है जिससे शिक्षा और रोजगार के मौके साथ-साथ मिल सकें।

महात्मा गांधी हैंडलूम योजना

वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 2,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की घोषणा की है। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को दोबारा सक्रिय करने और लघु उद्योगों को मजबूती देने के लिए 7,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, हथकरघा और पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में 350 से अधिक सुधार लागू किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई और औद्योगिक विकास को गति देना है।

बायोफार्मा और उभरते औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नई नीतियां तैयार करने का भी प्रस्ताव रखा गया है, ताकि उच्च मूल्य वाले उत्पादन और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकें। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का बड़ा बजट आवंटन किया गया है, जिससे भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे लाने की कोशिश की जाएगी।

लखपति दीदी योजना को और मजबूती

सरकार ने बजट में सी मार्ट्स स्कीम को लॉंच करते हुए केंद्रीय बजट 2026 में लखपति दीदी योजना को अपग्रेड किया है। इसमें ग्रामीण महिलाओं को अपने कारोबार का मालिक बनाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत सी मार्ट्स शुरू करने का भी ऐलान किया गया। केंद्र सरकार की महिलाओं को मजबूत बनाने की प्रमुख योजना लखपति दीदी योजना को केंद्रीय बजट 2026 में एक बड़ा सुधार देखने को मिला। इसके तहत महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए समुदाय के स्वामित्व वाले सी-मार्ट्स के विस्तार का प्रस्ताव रखा गया है।

लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को सिर्फ कर्ज से जुड़े रोज़गार तक सीमित न रखकर उन्हें अपने कारोबार का मालिक बनने में मदद करने का प्रस्ताव किया गया है। सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर (सी) मार्ट्स को क्लस्टर स्तर के संघों के भीतर समुदाय के स्वामित्व वाले रिटेल स्टोर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिन्हें बेहतर और नए तरह के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया जाएगा।

क्या है लखपति दीदी योजना?

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई लखपति दीदी योजना का उद्देश्य सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को छोटे कारोबार शुरू करने और हर साल कम से कम 1 लाख रुपये की स्थायी आमदनी कमाने में मदद करना है, ताकि वे आर्थिक रूप से खुद पर निर्भर बन सकें। यह कार्यक्रम महिलाओं को सिलाई और प्लंबिंग से लेकर एलईडी बल्ब बनाने और ड्रोन उड़ाने जैसे कई तरह के कौशलों की ट्रेनिंग देता है और ऐसे रोज़गार को बढ़ावा देता है जिससे परिवार की आय बढ़ सके। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में कहा था कि देशभर में सीज से जुड़ी 10 करोड़ महिलाओं की ताकत के जरिये 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का उनका सपना है। हाल के वर्षों में इस योजना का दायरा बढ़ा है और सरकार के लक्ष्य शुरुआती लक्ष्य से भी आगे निकल गए हैं, जिससे साफ होता है कि यह योजना जमीनी स्तर पर महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है।

दखल

मेडिकल टूरिज्म हब

सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश में पांच क्षेत्रीय मेडिकल टूरिज्म हब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इन हब्स में अस्पताल, डायग्नोस्टिक सुविधाएं और आयुष (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) को एक साथ जोड़ा जाएगा, ताकि विदेशों से आने वाले मरीजों को आकर्षित किया जा सके।

एआई से स्किल, रोजगार और ग्रोथ को मिलेगा बूस्ट

वित्त मंत्री ने कहा कि कटिंग एज टेक्नोलाजीज यानी अत्याधुनिक तकनीकें, खासकर एआई, आने वाले समय में आर्थिक विकास को कई गुना बढ़ाने का काम करेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि एआई का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, सिर्फ टेक कंपनियों तक सीमित न रहे। किसानों के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर, महिलाओं के लिए डिजिटल स्किल और युवाओं के लिए नए टेक जॉब अवसर तैयार करने पर जोर दिया गया है। एआई आधारित स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ट्रेनिंग मॉडल को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि नई टेक्नोलॉजी लोगों की उत्पादकता बढ़ाए और उन्हें बेहतर कमाई के अवसर दे।

खुलेंगे 5 बड़े 'मेडिकल हब', तीन नए एम्स

बजट 2026 में मरीजों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है, जिससे इलाज का खर्च काफी कम हो जाएगा। इसके अलावा, देश में 3 नए एम्स और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब खोले जाएंगे। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के साथ ही 1.5 लाख युवाओं को हेल्थ सेक्टर में ट्रेनिंग देने की भी घोषणा हुई है।

सस्ती होंगी जान बचाने वाली दवाएं

अक्सर देखा गया है कि घर में किसी को कैंसर या डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी होने पर पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है। वित्त मंत्री ने इस दर्द को समझते हुए ऐलान किया है कि अब कैंसर और शुगर (मधुमेह) की दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। यह कदम मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है।

सरकार का यह फैसला न केवल मरीजों का वित्तीय बोझ कम करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि पैसे की कमी के कारण किसी का इलाज न रुके। इसके अलावा, दवा निर्माण के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'बायो-फार्मा शक्ति" योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 10,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश किया जाएगा।

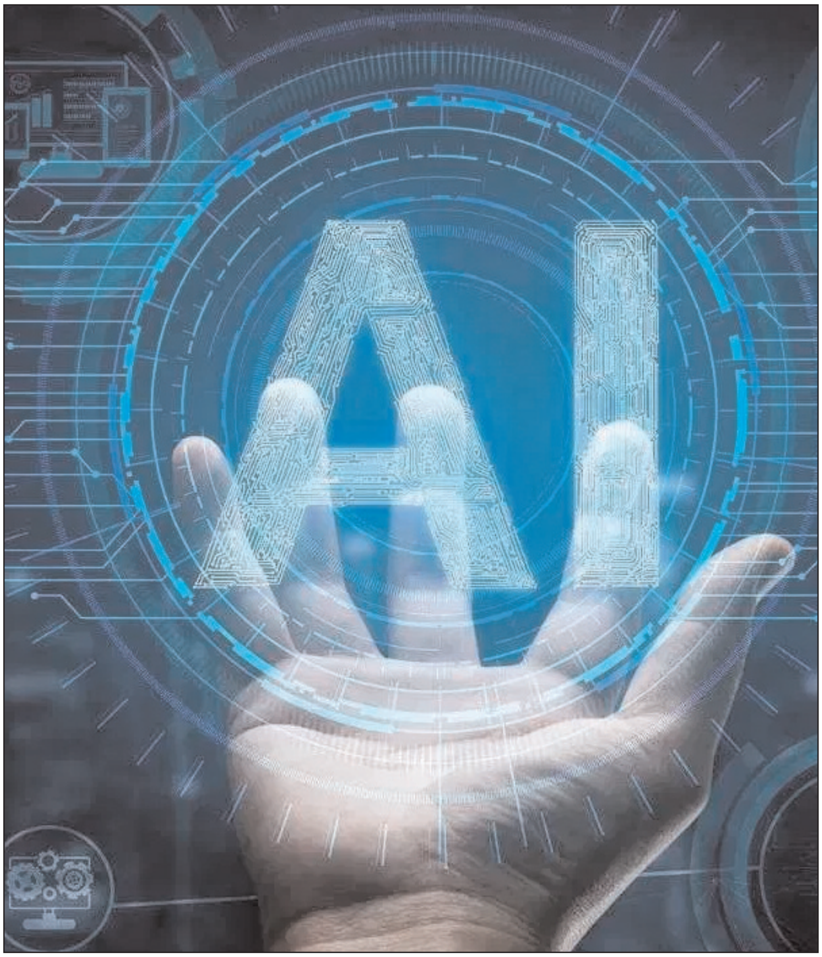

इसके अलावा, इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों की दौड़ लगाने वाले लोगों के लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) बनाने की घोषणा की है। इन नए एम्स के खुलने से देश के दूर-दराज के इलाकों में भी वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधाएं मिल सकेंगी।

यही नहीं, सरकार ने 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब (रीजनल मेडिकल हब) स्थापित करने का भी फैसला किया है। इन हब्स का उद्देश्य केवल इलाज करना नहीं, बल्कि मेडिकल रिसर्च और ट्रेनिंग को भी बढ़ावा देना है। इन केंद्रों पर स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी और ये मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगे। सरकार की योजना है कि इन हब्स के जरिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए जाएं।

आयुर्वेद को मिलेगी ग्लोबल पहचान

अब आयुर्वेद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने की तैयारी है। पारंपरिक दवाओं पर शोध को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के जामनगर में एक विशेष संस्थान स्थापित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति में कई गंभीर रोगों का इलाज छिपा है, जिसे अब दुनिया के सामने लाया जाएगा।

रोजगार के मोर्चे पर भी हेल्थ सेक्टर में बड़ी खबर है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 1.5 लाख केयर गिवर्स (देखभाल करने वाले सहायकों) को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में नर्सिंग और पेशेंट केयर के क्षेत्र में युवाओं के लिए नौकरियों की बहार आने वाली है।

-लेखक ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका की समाचार संपादक हैं

विष्णु स्वरूप

होली है...! डरिए नहीं, गुजिया और मालपुआ, दिल खोल कर सब खाइए...

लेकिन, मिलावटी मावा, दूध और मेवों से सावधान

होली भारत का एक प्रमुख और उल्लासपूर्ण त्योहार है, जो रंगों, उमंग और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग एक-दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं और विविध प्रकार -के व्यंजन जैसे, गुजिया, मठरी, दही-बड़े, ठंडाई, कचौरी, मालपुआ, लड्डू आदि का आनंद लेते हैं।

बाजारों में मिठाइयों और नमकीन की बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। मांग बढ़ने के साथ-साथ कुछ असामाजिक तत्व अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से खाद्य पदार्थों में मिलावट कर देते हैं। यह मिलावट न केवल त्योहार की खुशियों को फीका कर देती है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा भी बन सकती है। खाद्य मिलावट से फूड पॉयजनिंग, एलर्जी, पेट संबंधी रोग, लीवर और किडनी की समस्याएं , यहां तक कि दीर्घकालीन बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम होली के अवसर पर खानपान में होने वाली सामान्य मिलावटों को समझें और उनसे बचने के लिए उचित सावधानियां बरतें।

होली पर बढ़ती मांग और मिलावट का कारण

होली के दौरान मिठाइयों, दूध, मावा (खोया), सूखे मेवों और मसालों की मांग अचानक बढ़ जाती है। कई बार उत्पादन क्षमता सीमित होती है, जबकि उपभोक्ता की मांग अधिक होती है। ऐसे में कुछ व्यापारी

- नकली या सिंथेटिक मावा तैयार करते हैं।
- पुराने या बासी खाद्य पदार्थों को ताजा बताकर बेचते हैं।
- रंग और सुगंध बढ़ाने के लिए कृत्रिम रसायनों का उपयोग करते हैं।
- वजन बढ़ाने के लिए सस्ते पदार्थ मिला देते हैं।

तेजी से लाभ कमाने की यह प्रवृत्ति उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ करती है।

- बच्चे और बूढ़े खाने के मामले में अपनी हद में रहें
- ठंडई में भांग भी होती है पता करके पिएं

होली पर होने वाली आम मिलावट मावा (खोया) और उससे बनी मिठाइयां

मिलावट के तरीके

- सिंथेटिक मावा, जिसमें स्टार्च, मैदा, वनस्पति घी और रिफाइंड तेल मिलाया जाता है।
- यूरिया, डिटर्जेंट या कृत्रिम दूध पाउडर का प्रयोग।
- बासी मावे को दोबारा गर्म करके बेचना।

स्वास्थ्य पर प्रभाव

- पेट दर्द, उल्टी-दस्त
- किडनी और लीवर पर दुष्प्रभाव
- बच्चों और बुजुर्गों में गंभीर संक्रमण

दूध और दूध उत्पाद

होली पर ठंडाई, रबड़ी, दही-बड़े आदि में दूध का अधिक उपयोग होता है।

मिलावट

- पानी मिलाना (गाढ़ापन कम करने के लिए)
- डिटर्जेंट और सिंथेटिक केमिकल
- यूरिया या स्टार्च
- सिंथेटिक दूध

दुष्प्रभाव

- पाचन तंत्र में गड़बड़ी
- एलर्जी
- दीर्घकालीन अंग क्षति

सूखे मेवे

सावधान

गुजिया, हलवा और ठंडाई में काजू, बादाम, पिस्ता आदि का प्रयोग होता है।

मिलावट के तरीके

- पुराने या कीड़े लगे मेवों को पॉलिश कर बेचना
- काजू की जगह मूंगफली के टुकड़े
- कृत्रिम रंग और चमक के लिए रसायन

क्या हैं खतरे

- फूड पॉयजनिंग
- फंगल संक्रमण
- एलर्जी

मसाले और रंग

ठंडाई और मिठाइयों में केसर, इलायची, हल्दी आदि डाली जाती है।

मिलावट

- असली केसर की जगह रंगे हुए धागे
- हल्दी में मेटानिल येलो (हानिकारक रंग)
- मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा

स्वास्थ्य पर प्रभाव

- पेट में जलन
- त्वचा एलर्जी
- कैंसरकारी प्रभाव (लंबे समय में)

मिठाइयां और नमकीन मिलावट का खतरा:

- कृत्रिम रंग (टार्ट्राजीन आदि)
- सस्ता तेल या बार-बार उपयोग किया गया तेल
- सिंथेटिक सुगंध

हानि

- हृदय रोग का खतरा
- कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि
- कैंसरकारी तत्वों का प्रवेश

ठंडाई और पेय पदार्थ

होली पर ठंडाई विशेष पेय है।

मिलावट

- कृत्रिम फ्लेवर
- अधिक मात्रा में सिंथेटिक रंग
- बर्फ में गंदा पानी

> **रंगों में कैमिकल मिला है, आंख-मुंह में न जाए**
>
> **होली मनाएं लेकिन सावधानी भी जरूरी**

परिणाम

- संक्रमण
- डायरिया
- टायफाइड जैसे रोग

आप मिलावट की पहचान कैसे करेंगे

- **मावा परीक्षण :** थोड़ा मावा हथेली पर रगड़ें। यदि अत्यधिक चिकनाहट और अजीब गंध आए तो शक करें।

आयोडीन की कुछ बूंद डालें, नीला रंग आए तो स्टार्च की मिलावट है।

- **दूध परीक्षण :** दूध की एक बूंद सपाट सतह पर डालें, यदि वह तेजी से फैल जाए तो पानी मिला हो सकता है।

झाग अधिक बने और देर तक रहे तो डिटर्जेंट की आशंका।

- **हल्दी परीक्षण :** पानी में हल्दी घोलें, यदि तलछट में अलग रंग दिखे तो मिलावट संभव।
- **केसर परीक्षण:** असली केसर पानी में धीरे-धीरे रंग छोड़ता है, तुरंत गहरा रंग आना मिलावट का संकेत है।

क्या सावधानियां बरतें? विश्वसनीय दुकान से खरीदें

- केवल लाइसेंसधारी दुकानों से मिठाई खरीदें।
- FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) का लाइसेंस नंबर देखें।
- बिल अवश्य लें।

पैक्ड और ब्रांडेड उत्पाद को प्राथमिकता दें

- पैकिंग पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी तिथि जांचें।
- खुली मिठाइयों के बजाय सीलबंद उत्पाद लें।

घर पर बनाएं

हो सके तो गुजिया, नमकीन, ठंडाई आदि घर पर तैयार करें। इससे शुद्धता सुनिश्चित होगी।

रंग और सुगंध से सावधान

बहुत चमकीले रंग वाली मिठाइयाँ न खरीदें। प्राकृतिक रंगों को प्राथमिकता दें।

सीमित मात्रा में खरीदें

अधिक मात्रा में खरीदने से बासी होने की संभावना बढ़ती है।

स्वच्छता का ध्यान रखें

- मिठाई खरीदते समय दुकान की साफ-सफाई देखें।
- खुले में रखी मिठाई से बचें।

यदि मिलावट का संदेह हो तो, शिकायत दर्ज कराएं

- FSSAI हेल्पलाइन (1800-11-2100) पर शिकायत करें।
- Food Safety Connect ऐप का उपयोग करें।
- स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सूचना दें।

स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सुझाव

- मधुमेह और हृदय रोगी सीमित मात्रा में मिठाई खाएं।
- बच्चों को अधिक रंगीन और सस्ती मिठाइयों से दूर रखें।
- पर्याप्त पानी पिएं।
- संतुलित आहार अपनाएं।

होली का त्योहार खुशियों और भाईचारे का प्रतीक है। किंतु खानपान में मिलावट इस आनंद को कड़वा बना सकती है। थोड़ी सी लापरवाही गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। आवश्यक है कि हम सजग उपभोक्ता बनें, खरीदारी में सावधानी बरतें और मिलावट के खिलाफ आवाज उठाएं।

बच के रहो मिलावटी रंगों से

होली रंगों का त्योहार है, लेकिन आज बाजार में बिकने वाले कई रंग प्राकृतिक न होकर रासायनिक (सिंथेटिक) होते हैं। सस्ते और चटकीले रंग बनाने के लिए औद्योगिक डाई, भारी धातुएं और अन्य हानिकारक रसायन मिलाए जाते हैं। ये रंग त्वचा, आंख, श्वसन तंत्र और लंबे समय में आंतरिक अंगों तक पर बुरा असर डाल सकते हैं।

लेड ऑक्साइड (Lead Oxide) – काला रंग

कहां मिलता है : सस्ते काले या गहरे रंगों में

प्रभाव

- त्वचा पर जलन और एलर्जी
- आंखों में जलन, दृष्टि पर असर
- लंबे समय में लेड विषाक्तता (Lead Poisoning)
- बच्चों में मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव
- किडनी और तंत्रिका तंत्र को नुकसान

मरकरी सल्फाइड (Mercury Sulphide) – लाल रंग

कहां मिलता है : चमकीले लाल रंगों में

प्रभाव

- त्वचा पर चकत्ते और खुजली
- त्वचा कैंसर का खतरा (दीर्घकाल में)
- तंत्रिका तंत्र पर दुष्प्रभाव
- किडनी डैमेज

क्रोमियम आयोडाइड (Chromium Iodide) – हरा रंग

कहां मिलता है : सस्ते हरे गुलाल में

प्रभाव

- त्वचा पर एलर्जिक डर्मेटाइटिस
- आंखों में जलन
- अस्थमा रोगियों में सांस लेने में कठिनाई
- लंबे समय में कैंसर का जोखिम

कॉपर सल्फेट (Copper Sulphate) – नीला रंग

कहां मिलता है : नीले रंग के पाउडर में

प्रभाव

- आंखों में तेज जलन
- अस्थायी अंधापन
- त्वचा पर जलन
- उल्टी और पेट दर्द (यदि शरीर में प्रवेश करे)

एल्यूमिनियम ब्रोमाइड – चांदी जैसा रंग

प्रभाव

- त्वचा में सूजन
- तंत्रिका तंत्र पर दुष्प्रभाव
- लंबे समय में न्यूरोलॉजिकल समस्याएं

औद्योगिक डाई और सस्ते सिंथेटिक रंग

कई रंग कपड़ा उद्योग में इस्तेमाल होने वाले डाई से बनाए जाते हैं।

प्रभाव

- गंभीर एलर्जी
- त्वचा का रंग बदलना
- बालों का झड़ना
- आंखों में संक्रमण

बच्चों और बुजुर्गों को अधिक खतरा

बच्चों की त्वचा पतली और संवेदनशील होती है, इसलिए उन्हें अधिक नुकसान हो सकता है।

बुजुर्गों और पहले से बीमार व्यक्तियों में एलर्जी और श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

पर्यावरण पर प्रभाव

- रसायनयुक्त रंग पानी के स्रोतों को प्रदूषित करते हैं।
- मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- पशु-पक्षियों को हानि पहुंचती है।
- जलीय जीवों की मृत्यु हो सकती है।

आपको क्या सावधानी बरतनी है

हर्बल और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें

- हल्दी, चंदन, गुलाब की पंखुड़ी
- मेहंदी पाउडर
- चुकंदर का रस
- टेसू (पलाश) के फूल

त्वचा की सुरक्षा

- रंग खेलने से पहले नारियल या सरसों का तेल लगाएं
- फुल स्लीव कपड़े पहनें
- सनग्लास का प्रयोग करें

आंख और मुंह की सुरक्षा

- आंखों में रंग न जाने दें
- मुंह बंद रखें
- छोटे बच्चों को जबरदस्ती रंग न लगाएं

रंग. खेलने के बाद

- हल्के साबुन से नहाएं
- त्वचा को मॉइस्चराइज करें
- आंखों में जलन हो तो तुरंत पानी से धोएं

होली का आनंद तभी सार्थक है जब वह सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से मनाई जाए। सस्ते और रासायनिक रंगों की चमक भले आकर्षक लगे, लेकिन उनके दुष्प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। जागरूकता और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है।

-लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
International Year of Cooperatives
2025
Cooperatives Build a Better World
जब तकनीक और प्रकृति हों साथ,
तब हम कहलाते हैं
प्रगति की खाद
नैनो यूरीया
नैनो डीएपी
नैनो कॉपर
नैनो ज़िंक
IFFCO NANO UREA PLUS
IFFCO NANO DAP
IFFCO NANO COPPER (0.8% Cu w/w)
IFFCO NANO ZINC (1.0% Zn w/w)

बिनोद आशीष

राहत कम-वादा ज्यादा

आम उपभोक्ता के सवाल

रसोई, स्कूल की फीस, ईएमआई पर कितनी मिली राहत?

फरवरी के शुरू होने के साथ संसद में आम बजट पेश किया गया। बजट को लेकर कई तरह की धारणाएं बनीं। कई मामलों में रियायतें मिलीं तो कई में बजट अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा। राजनीतिक बयानबाजी से इतर विशेषज्ञों ने बजट को परखने की कोशिश की। उनकी भी बजट पर अलग-अलग राय सामने आई। कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट में वादे तो बहुत से किए गए हैं लेकिन इससे एक आम आदमी को सीधे तौर पर राहत मिलती कम दिखती है। ग्रामीण उपभोक्ता के इस अंक में एक आम उपभोक्ता के नफे-नकसान के परिप्रेक्ष्य में आम बजट को मापने की कोशिश की गई है।

आम उपभोक्ता और बजट का गणित

भारत में आम बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह करोड़ों लोगों की उम्मीदों, आशंकाओं और रोज़मर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ा होता है। संसद में पेश होने वाला बजट जब कागज से निकलकर बाजार, बैंक, रसोई, पेट्रोल पंप, स्कूल फीस और अस्पताल के बिल तक पहुंचता है, तब उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। आम उपभोक्ता के लिए बजट का अर्थ है-महंगाई कम होगी या बढ़ेगी? नौकरी के अवसर बढ़ेंगे या घटेंगे? टैक्स में राहत मिलेगी या बोझ बढ़ेगा? रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती होंगी या महंगी?

आम बजट 2026-27 भी इन्हीं सवालों के बीच आया है। सरकार ने इसे विकासोन्मुख, पूंजीगत निवेश आधारित और मध्यम वर्ग के लिए राहतकारी बजट बताया है। लेकिन आम उपभोक्ता की दृष्टि से इसकी समीक्षा करते समय हमें यह देखना होगा कि घोषणाएं और वास्तविक प्रभाव में कितना अंतर है।

आयकर राहत : जेब में कितना बचेगा?

बजट में नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को और आकर्षक बनाने के लिए आयकर स्लैब में कुछ बदलाव किए गए हैं। बेसिक छूट सीमा बढ़ाने और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की घोषणा को मध्यम वर्ग के लिए राहत बताया गया है।

आम उपभोक्ता पर प्रभाव

> **▸ रोजगार, अस्पताल के बिल और महंगाई का क्या होगा?**
> **▸ टैक्स में दी गई राहत का बड़ा हिस्सा महंगाई खा जाती**

- **मध्यम वर्गीय वेतनभोगी:** जिनकी सालाना आय 6-12 लाख के बीच है, उन्हें कुछ हजार से लेकर लगभग 20,000 से 30,000 तक की वार्षिक बचत हो सकती है। यह राशि सुनने में बड़ी लग सकती है, लेकिन जब महंगाई दर 5-6% के आसपास हो, तब वास्तविक बचत सीमित हो जाती है।
- **निम्न आय वर्ग:** जिनकी आय कर दायरे में ही नहीं आती, उनके लिए इस राहत का कोई सीधा लाभ नहीं है।
- **उच्च आय वर्ग:** सरचार्ज और अन्य

प्रावधानों में मामूली बदलाव से उन्हें सीमित राहत मिलती है।

समीक्षात्मक दृष्टि

आम उपभोक्ता की दृष्टि से आयकर राहत सकारात्मक है, परंतु यह सवाल बना रहता है कि क्या यह राहत बढ़ती शिक्षा फीस, स्वास्थ्य खर्च और ईएमआई के बोझ को संतुलित कर पाएगी? यदि मुद्रास्फीति उच्च बनी रहती है, तो टैक्स में दी गई राहत का बड़ा हिस्सा महंगाई खा जाती है।

महंगाई और रोजमर्रा की चीजें

आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता रसोई से जुड़ी होती है। दाल, तेल, सब्जी, गैस सिलेंडर, दूध-ये सब सीधे परिवार के बजट को प्रभावित करते हैं।

पेट्रोल और डीजल

बजट में उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में बड़े बदलाव नहीं किए गए। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं, तो घरेलू कीमतें भी स्थिर रह सकती हैं। लेकिन यदि वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं, तो आम उपभोक्ता पर बोझ बढ़ना तय है।

रसोई गैस

LPG सब्सिडी को सीमित दायरे में रखा गया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को आंशिक राहत मिलती है, पर मध्यम वर्ग को बाजार दर पर गैस खरीदनी पड़ती है।

खाद्य पदार्थ

सरकार ने कृषि और भंडारण ढांचे में निवेश बढ़ाने की बात कही है, जिससे दीर्घकाल में कीमतों में स्थिरता आ सकती है। परंतु अल्पकाल में मौसम, आपूर्ति और वैश्विक कारकों पर निर्भरता बनी रहती है।

समीक्षात्मक दृष्टि

आम उपभोक्ता के लिए बजट में महंगाई पर सीधी और ठोस राहत के संकेत सीमित हैं। दीर्घकालिक उपायों की बात की गई है, पर तत्काल राहत कम दिखाई देती है।

रोजगार और कमाई के अवसर

बजट में पूंजीगत व्यय लगभग 11-12 लाख करोड़ रखा गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है।

इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रोजगार सृजन करना है।

संभावित लाभ

- सड़क, रेलवे, निर्माण क्षेत्र में अस्थायी और स्थायी नौकरियों में वृद्धि
- MSME सेक्टर को क्रेडिट गारंटी से समर्थन
- स्टार्टअप और डिजिटल सेक्टर में अवसर

वास्तविकता

आम उपभोक्ता के लिए सवाल है- क्या ये नौकरियां स्थायी और सम्मानजनक वेतन वाली होंगी?

यदि रोजगार असंगठित क्षेत्र में ही सीमित रहता है, तो आय में स्थिरता नहीं आती।

CMIE के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर 7-8% के आसपास बनी हुई है। ऐसे में बजट की घोषणाएं तभी सार्थक होंगी जब वे वास्तविक रोजगार में बदलें।

शिक्षा पर खर्च : परिवार के बजट का बड़ा हिस्सा

शिक्षा मंत्रालय को लगभग 1.3-1.4 लाख करोड़ का आवंटन मिला है। डिजिटल शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और नई यूनिवर्सिटी की घोषणाएं की गई हैं।

आम उपभोक्ता की चिंता

- निजी स्कूलों की फीस लगातार बढ़ रही है
- कोचिंग और ऑनलाइन शिक्षा पर अतिरिक्त खर्च
- उच्च शिक्षा की फीस और छात्र ऋण का

बोझ

सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता सुधार की दिशा में कदम सकारात्मक हैं, परंतु मध्यम वर्ग अभी भी निजी संस्थानों पर निर्भर है।

समीक्षात्मक दृष्टि

जब तक शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता में व्यापक सुधार नहीं होगा, तब तक परिवारों पर शिक्षा खर्च का बोझ कम नहीं होगा।

सेहत का सवाल: जेब से होने वाला खर्च

स्वास्थ्य बजट में वृद्धि की गई है और आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया गया है।

बैंकिंग, ईएमआई और ब्याज दरें

बजट का सीधा असर ब्याज दरों पर नहीं होता, पर राजकोषीय घाटा और सरकारी उधारी अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं।

- यदि घाटा नियंत्रित रहता है, तो ब्याज दरों पर दबाव कम होगा।
- होम लोन और वाहन लोन की ईएमआई स्थिर रह सकती है।

मध्यम वर्ग के लिए यह राहत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर और गाड़ी की ईएमआई परिवार के मासिक खर्च का बड़ा हिस्सा होती है।

डिजिटल भुगतान और उपभोक्ता अधिकार

सरकार ने डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन लेन-देन को बढ़ावा दिया है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है, पर साइबर फ्रॉड की घटनाएं भी बढ़ी हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और ई-कॉमर्स नियमों को सख्त बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

यह आम उपभोक्ता के लिए सकारात्मक संकेत है।

सकारात्मक पहलू

- गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज
- नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल

सीमाएं

- मध्यम वर्ग के लिए निजी अस्पतालों का खर्च बहुत ज्यादा
- बीमा कवरेज सीमित
- दवाओं की कीमतें ऊंची

भारत में अभी भी स्वास्थ्य पर जेब से होने वाला निजी खर्च कुल स्वास्थ्य खर्च का लगभग 50% से अधिक है। जब तक यह अनुपात कम नहीं होता, आम उपभोक्ता पर बोझ बना रहेगा।

महिला और परिवार केंद्रित योजनाएं

महिला एवं बाल विकास के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। पोषण, मातृत्व लाभ और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिला है।

इससे ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को लाभ हो सकता है।

परंतु शहरी मध्यम वर्ग के लिए प्रत्यक्ष लाभ सीमित है।

हरित ऊर्जा और बिजली बिल

ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश से दीर्घकाल में बिजली सस्ती हो सकती है। घरेलू सोलर पैनल पर सब्सिडी योजनाएं उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद हो सकती हैं।

सामाजिक सुरक्षा और बुजुर्ग

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ कर छूट और पेंशन योजनाओं में सुधार किए गए हैं।

यह सीमित आय वाले बुजुर्गों के लिए राहतकारी कदम है।

आम उपभोक्ता क्या महसूस करेगा?

सकारात्मक पक्ष

- आयकर में आंशिक राहत
- इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से संभावित रोजगार
- स्वास्थ्य और शिक्षा में बजटीय वृद्धि
- डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था पर फोकस

नकारात्मक और चिंताजनक पक्ष

- महंगाई पर तत्काल राहत का अभाव
- बेरोजगारी की समस्या का स्पष्ट समाधान नहीं
- शिक्षा और स्वास्थ्य का निजी खर्च अभी भी ऊंचा
- ग्रामीण आय में ठोस वृद्धि के संकेत सीमित

आम बजट 2026-27 को यदि आम उपभोक्ता की नजर से देखें, तो यह पूरी तरह निराशाजनक नहीं है, पर अत्यधिक राहतकारी भी नहीं है। यह दीर्घकालीन विकास की दिशा में एक प्रयास है, पर तत्काल राहत सीमित है। मध्यम वर्ग को कुछ कर राहत मिली है, गरीब वर्ग को सामाजिक योजनाओं से समर्थन मिला है, पर महंगाई और रोजगार की चुनौती अब भी बड़ी है। आम उपभोक्ता के लिए यह बजट संभावनाओं का दस्तावेज अधिक है, तत्काल राहत का पैकेज कम। यदि घोषणाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू होती हैं और निजी निवेश तथा रोजगार में वास्तविक वृद्धि होती है, तो आने वाले वर्षों में इसका लाभ दिखाई दे सकता है। अन्यथा, यह बजट भी उन कई बजटों की तरह इतिहास में दर्ज हो जाएगा जिनमें वादे अधिक और प्रत्यक्ष राहत कम रही।

समग्र आर्थिक परिदृश्य

- **कुल व्यय (Total Expenditure):** लगभग 48-49 लाख करोड़
- **कुल प्राप्तियां (Total Receipts, उधार छोड़कर):** लगभग 33-34 लाख करोड़
- **राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit):** जीडीपी का लगभग 4.5-4.8%
- **जीडीपी अनुमान:** लगभग 330-340 लाख करोड़
- **पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure):** 11-12 लाख करोड़ (लगभग 3.5% जीडीपी)

सरकार ने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए पूंजीगत निवेश बढ़ाने की नीति जारी रखी है। राजकोषीय घाटा धीरे-धीरे 4.5% के आसपास लाने का लक्ष्य मध्यम अवधि के राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) रोडमैप का हिस्सा है।

कर राजस्व और प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes)

- **कॉरपोरेट टैक्स संग्रह अनुमान:** 11-12 लाख करोड़
- **व्यक्तिगत आयकर संग्रह:** 12-13 लाख करोड़
- व्यक्तिगत आयकर में नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को और आकर्षक बनाया गया है।
- बेसिक छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख से 6 लाख करने पर विचार/प्रावधान।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 तक।

इससे मध्यम वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है।

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes)

- **जीएसटी संग्रह लक्ष्य:** 10-11 लाख करोड़

पेट्रोलियम और तंबाकू उत्पादों पर सेस में मामूली संशोधन।

जीएसटी संग्रह में पिछले वर्षों की तरह स्थिर वृद्धि (मासिक औसत 1.7 लाख करोड़ के आसपास) को आधार बनाया गया है।

कृषि और ग्रामीण विकास

- कृषि मंत्रालय आवंटनः 1.6-1.8 लाख करोड़
- PM-KISAN के लिए 60,000 करोड़
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः 15,000-18,000 करोड़
- कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का विस्तार

सरकार ने प्राकृतिक खेती, ड्रोन तकनीक और कृषि स्टार्टअप्स पर विशेष बल दिया है।

ग्रामीण सड़कों (PMGSY) और ग्रामीण आवास (PM Awas Gramin) के लिए आवंटन में 10-15% वृद्धि की गई है।

समीक्षा

कृषि में आय दोगुनी करने का लक्ष्य अभी भी चुनौतीपूर्ण है। बजट में निवेश तो बढ़ा है, पर MSP पर कानूनी गारंटी जैसे मुद्दे अनसुलझे हैं।

शिक्षा

- शिक्षा मंत्रालय कुल आवंटनः 1.3-1.4 लाख करोड़
- स्कूली शिक्षाः 80,000 करोड़
- उच्च शिक्षाः 50,000 करोड़ से अधिक
- डिजिटल यूनिवर्सिटी और स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के क्रियान्वयन हेतु डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, AI आधारित शिक्षा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) पर विशेष जोर।

समीक्षा

GDP के अनुपात में शिक्षा पर व्यय अभी भी लगभग 3% के आसपास है, जबकि लक्ष्य 6% है। यह अंतर नीति-लक्ष्य और वास्तविकता के बीच का फासला दिखाता है।

स्वास्थ्य

- स्वास्थ्य बजटः 90,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच
- आयुष्मान भारत विस्तार
- 200 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा
- टीकाकरण और डिजिटल हेल्थ मिशन को प्रोत्साहन

समीक्षा

स्वास्थ्य पर व्यय अभी भी GDP का लगभग 2% है, जबकि WHO की सिफारिश 5% है। बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है, पर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में कमी बनी हुई है।

अवसंरचना (Infrastructure)

- पूंजीगत व्ययः 11-12 लाख करोड़
- रेलवे के लिए 2.8-3 लाख करोड़
- सड़क परिवहन और राजमार्गः 2.5 लाख करोड़
- 100 नए लॉजिस्टिक पार्क और मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क

सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि का मुख्य इंजन बनाया है।

सकारात्मक पक्ष

- निजी निवेश को आकर्षित करने की संभावना
- निर्माण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि

चुनौती

- राज्यों की वित्तीय स्थिति कमजोर
- PPP मॉडल में निजी भागीदारी सीमित

सामाजिक क्षेत्र और कल्याण योजनाएं

- महिला एवं बाल विकासः 30,000-35,000 करोड़
- पोषण अभियान और लाडली लक्ष्मी/बेटी बचाओ जैसी योजनाओं को बढ़ावा
- बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि

गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

रोजगार और उद्योग

- MSME सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में विस्तार

- स्टार्टअप इंडिया के लिए टैक्स छूट की अवधि बढ़ाई गई
- PLI (Production Linked Incentive) योजना का बजट 1.5 लाख करोड़ से अधिक

सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।

समीक्षा

रोजगार सृजन के स्पष्ट आंकड़े सीमित हैं। बेरोजगारी दर (CMIE के अनुसार 7-8%) अभी भी चिंता का विषय है।

रक्षा और आंतरिक सुरक्षा

- रक्षा बजटः 6.5-7 लाख करोड़
- स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर
- सीमा अवसंरचना विकास में वृद्धि

हरित अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन

- ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 20,000 करोड़
- इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सब्सिडी जारी
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विशेष प्रावधान

भारत ने 2070 नेट-जीरो लक्ष्य की दिशा में बजटीय समर्थन बढ़ाया है। आम बजट 2026-27 विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति देने की रणनीति पर आधारित है। मध्यम वर्ग और उद्योग जगत को कुछ राहत मिली है, परंतु शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन जैसे सामाजिक क्षेत्रों में अभी और साहसिक कदमों की आवश्यकता है।

सस्ता-महंगा

कौन-सी चीजें सस्ती हुई?

- देश के आम बजट में ऐलान किया गया है कि, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां सस्ती होंगी। इससे लाखों मरीजों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है।
- मेक-इन-इंडिया अभियान को मजबूती देते हुए भारत में निर्मित स्मार्टफोन और टैबलेट के दामों में कमी आने की संभावना है। सरकार के इस कदम से न केवल घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी किफायती दरों पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे।
- बजट 2026-27 में खेल इक्विपमेंट को अधिक किफायती बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे युवाओं और खिलाड़ियों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का फोकस है कि इस बजट के बाद बाजार में खेल कूद के सामान और किफायती दामों में मिले।
- माइक्रोवेव ओवन के खास पार्ट्स पर अब बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।
- चमड़े के निर्यात में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास इनपुट्स को ड्यूटी-फ्री आयात की सुविधा दी गई है।
- बीईएसएस (बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी माफ की गई है।
- सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है।
- न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए आयात किए जाने वाले सामान पर 2035 तक

कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।

- एविएशन सेक्टर के पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी माफ की गई है।
- विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस की दर 5-20 फीसद से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है।
- विदेश में पढ़ाई के खर्च पर एलआरएस के तहत अब कम टीडीएस लगेगा।
- जूते के ऊपरी हिस्से के निर्यात के लिए जरूरी सामान को ड्यूटी-फ्री आयात की अनुमति दी गई है।
- एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़े उपकरणों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ की गई है।
- फ्रोजन टर्की मांस पर टैरिफ 30 फीसद से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- आर्टेमिया सिस्ट और कैंसर की कुछ दवाओं पर टैरिफ 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
- झींगा और श्रिम्प्स के चारे पर टैरिफ 15 प्रतिशत से घटाकर 5 फीसद किया गया है।
- बोने के लिए इस्तेमाल होने वाले बीज, फल पर टैरिफ 30 प्रतिशत से घटाकर 15 फीसद किया गया है।
- मखाना, भुने हुए मेवे और बीजों पर टैरिफ 150 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।
- रेयर अर्थ मिनरल, स्कैंडियम और यट्रियम (मिश्रित या मिश्र धातु) पर टैरिफ 5 फीसद से घटाकर 0 कर दिया गया है।
- मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछली पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।
- फॉस्फोरिक एसिड पर ड्यूटी 7.5 फीसद से घटाकर 5 फीसद कर दी गई है।

बजट में किन चीजों के दाम बढ़े?

छाते और उनके पार्ट्स (जैसे ट्रिमिंग और एक्सेसरीज़) पर अब 10 फीसद या 25 रुपये प्रति किलो (जो भी ज़्यादा हो) ड्यूटी लगेगी।

- फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर STT अब 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है।
- शराब, मिनरल्स और स्क्रैप की बिक्री पर टीसीएस अब 1 फीसदसे बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है
- क्रैनबेरी पर ड्यूटी 5 प्रतिशत और ब्लूबेरी पर 10 फीसद कर दी गई है।
- पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड पर ड्यूटी अब शून्य से बढ़ाकर 7.5 फीसद कर दी गई है।
- क्रैनबेरी से बने उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाकर 10 फीसद कर दी गई है।
- रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों पर ड्यूटी अब 5 फीसद कर दी गई है।
- चबाने वाला तंबाकू, ज़र्दा और गुटखा पर एनसीसीडी 25 फीसद से बढ़ाकर 60 फीसद कर दिया गया है।

-लेखक ग्रामीण उपभोक्ता के संपादक हैं

सत्यम

इनकम टैक्स में हेरफेर... घबराइये नहीं जेल नहीं जाएंगे...

टैक्सपेयर्स को गलती सुधारने का मौका

सरकार ने करदाताओं पर जताया भरोसा, जुर्माना भरके निपटा सकते हैं अपनी गलती

आम करदाताओं को बजट में बड़ी राहत मिली है। अब इनकम टैक्स छिपाने या गड़बड़ी मिलने पर जेल की सजा नहीं होगी, बल्कि सिर्फ जुर्माना भरकर मामला निपटाया जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेश यात्रा पर भी टीसीएस घटाकर 2 फीसदी कर दिया है, जिससे घूमना सस्ता होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगले महीने यानी अप्रैल 2026 से नया और सरल इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है।

अगर आप भी इनकम टैक्स के सख्त नियमों और स्क्रूटनी की प्रक्रियाओं से डरते थे, तो वित्त वर्ष 2026-27 का बजट आपके लिए राहत की बड़ी सांस लेकर आया है। वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करते हुए साफ कर दिया है कि सरकार अब टैक्सपेयर्स पर भरोसा जताने की नीति पर काम कर रही है। सबसे बड़ी घोषणा यह है कि अब इनकम टैक्स छिपाने पर जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी। इसके अलावा, विदेश यात्रा से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक के नियमों में आम आदमी की जेब और सहूलियत का पूरा ख्याल रखा गया है।

जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना

टैक्सपेयर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि सरकार ने इनकम टैक्स कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगर किसी करदाता की आय में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छिपाया गया है, तो अब उसे जेल की सजा नहीं होगी। ऐसे मामलों में केवल जुर्माना (पेनल्टी) भरकर मामला रफा-दफा किया जा सकेगा।

यह नया बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले 'नए इनकम टैक्स एक्ट" का हिस्सा होगा। सरकार का मकसद टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाना है, न कि करदाताओं को डराना। साथ ही, जिनके पास विदेशों में अघोषित संपत्ति है, उन्हें भी एक मौका दिया गया है। वे अगले 6 महीनों के भीतर डिस्क्लोजर स्कीम के तहत अपनी संपत्ति की जानकारी दे सकते हैं।

विदेश यात्रा और पढ़ाई पर बड़ा फायदा

अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं या अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, तो यह बजट आपकी जेब पर बोझ कम करने वाला है। पहले विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस (टीसीएस) की दरें काफी ऊंची थीं, जो 5% से लेकर 20% तक होती थीं। इससे बजट बिगड़ जाता था। अब सरकार ने इसे घटाकर सीधा 2% कर दिया है। चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर विदेश यात्रा का पैकेज, अब आपको केवल 2% टीसीएस देना होगा।

आईटीआर फाइलिंग में सुधार का मौका

अक्सर ऐसा होता है कि रिटर्न भरते समय कोई जानकारी छूट जाती है। पहले इसे सुधारना एक जटिल प्रक्रिया थी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अब 'रिवाइज्ड रिटर्न" भरने के लिए करदाताओं को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके लिए बस एक नाममात्र की फीस चुकानी होगी। समय सीमा को भी स्पष्ट कर दिया गया है। आईटीआर-1 और आईटीआर-2 भरने वाले करदाता 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे। वहीं, नॉन-ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट के लिए यह तारीख 31 अगस्त तय

सरकार अब टैक्सपेयर्स पर भरोसा जताने की नीति पर काम कर रही है। सबसे बड़ी घोषणा यह है कि अब इनकम टैक्स छिपाने पर जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी। इसके अलावा, विदेश यात्रा से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक के नियमों में आम आदमी की जेब और सहूलियत का पूरा ख्याल रखा गया है।

की गई है। इसके अलावा, छोटे करदाताओं के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट (लोअर/निल टीडीएस) हासिल करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑटोमैटिक हो जाएगी, जिसके लिए अब अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदना हुआ आसान

अब तक अगर कोई निवासी किसी एनआरआई (एनआरआई) से भारत में प्रॉपर्टी खरीदता था, तो टीडीएस काटने के लिए उसे 'टैन नंबर" (टेन) लेने की जरूरत पड़ती थी। यह एक आम खरीदार के लिए सिरदर्द जैसा था। बजट में इसे खत्म कर दिया गया है। अब प्रॉपर्टी खरीदार सीधे टीडीएस काट सकेगा और उसे अलग से टैन नंबर के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही, जिन निवेश

कों का पैसा कई कंपनियों में लगा है, उनके लिए फॉर्म 15 जी और 15 एच की प्रक्रिया सरल कर दी गई है। अब डिपॉजिटरी इन फॉर्म्स को स्वीकार कर सीधे संबंधित कंपनियों को भेज सकेंगी, जिससे निवेशकों का काम घर बैठे हो जाएगा।

बायोफार्मा हब बनाने की पहल

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बायोफार्मा के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए हेल्थ एडवांसमेंट के लिए बायोफार्मा स्ट्रेटेजी हेल्थकेयर में भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करेगी।

हेल्थ केयर के लिए ये हुए ऐलान

बजट में प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में 5 रीजनल मेडिकल हब के साथ राज्यों को सपोर्ट करने की स्कीम की घोषणा की। ये हब हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए अलग-अलग तरह के जॉब के मौके देंगे।

- तीन नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद
- ड्रग टेस्टिंग लैब को ऊंचे स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करना
- 1.5 लाख केयरगिवर्स को ट्रेनिंग देना
- मेडिकल टूरिज्म हब में आयुष सेंटर

बायोफार्मा के अलावा सरकार ने सेमीकंडक्टर के लिए 40 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना भी लॉन्च करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा।

वीबी-जीराम जी पर सरकार ने लगाई सबसे बड़ी बोली

सरकार ने 'वीबी-जीराम जी योजना को बजट का सबसे बड़ा हिस्सा दिया है। इसके लिए 95,692.31 करोड़ रुपए का भारी आवंटन किया गया है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल के मूल बजट 86,000 करोड़ रुपए से करें, तो यह एक बड़ी छलांग है।

सरकार यहीं नहीं रुकी, बल्कि मनरेगा के प्रोग्राम कंपोनेंट के लिए अलग से 30,000

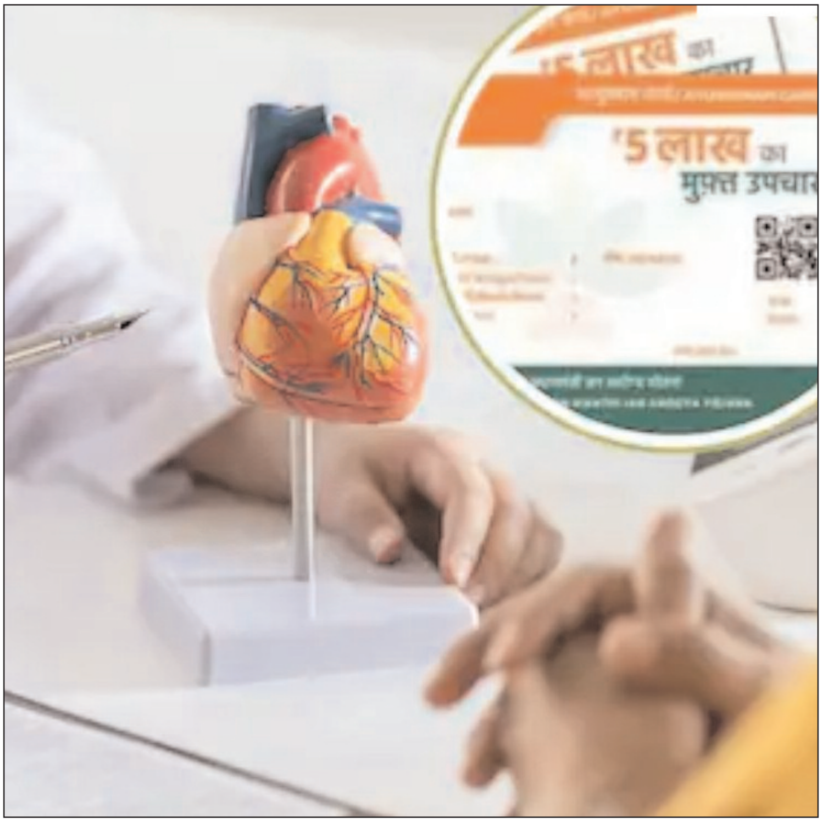

टैक्सपेयर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि सरकार ने इनकम टैक्स कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगर किसी करदाता की आय में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छिपाया गया है, तो अब उसे जेल की सजा नहीं होगी। ऐसे मामलों में केवल जुर्माना (पेनल्टी) भरकर मामला रफा-दफा किया जा सकेगा।

करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। इसका सीधा मतलब है कि गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जो मजदूर काम की तलाश में भटकते थे या जिन परिवारों को आर्थिक सहारे की जरूरत थी, उनके लिए यह राहत की खबर है।

खाने की थाली की चिंता खत्म

महामारी के बाद से शुरू हुई मुफ्त राशन की व्यवस्था अब गरीब परिवारों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) पर 2,27,429 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है।

यह आंकड़ा पिछले साल के 2.03 लाख करोड़ के बजट से काफी ज्यादा है। संशोधित अनुमानों में भी खर्च बढ़ा था, लेकिन इस बार का आवंटन यह बताता है कि सरकार किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश के किसी भी गरीब परिवार को राशन की दिक्कत न हो। करोड़ों परिवारों को मिलने वाला मुफ्त या सस्ता अनाज बदस्तूर जारी रहेगा।

आयुष्मान भारत के लिए खजाने से कितना निकला?

बीमारी का खर्च किसी भी मध्यम या गरीब परिवार की कमर तोड़ देता है। इसी चिंता को दूर करने वाली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए सरकार ने 9,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। पिछले साल के संशोधित अनुमान (8,995 करोड़) के मुकाबले इसमें थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। इस योजना का मकसद गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा देना है।

मानसिक स्वास्थ्य के लिए नया संस्थान

सरकार ने निम्हांस- दो जैसे नए मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंस संस्थान की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है। इससे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और रिसर्च को मजबूती मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने बजट 2026 के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत सेमीकंडक्टर के लिए उद्योग के नेतृत्व में रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटरों पर फोकस रहेगा। सेमीकंडक्टर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया गया। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-संपन्न राज्यों को समर्थन दिया जाएगा। राज्यों को तीन खास केमिकल पार्क स्थापित करने में मदद के लिए एक योजना शुरू की जाएगी, जिससे देश में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।

क्यों जरूरी सेमीकंडक्टर

सेमीकंडक्टर भारत के लिए बहुत जरूरी हैं क्योंकि आज की लगभग हर आधुनिक तकनीक इन्हीं पर चलती है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कार, वॉशिंग मशीन, एसी, इंटरनेट डिवाइस सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती हैं। अभी भारत ज्यादातर चिप्स विदेशों से मंगाता है। अगर देश में ही चिप बनेगी तो खर्च कम होगा और सप्लाई रुकने का खतरा भी नहीं रहेगा। सेमीकंडक्टर के लिए भारत सबसे ज्यादा चीन पर निर्भर है।

देश में सेमीकंडक्टर बनने से इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, ऑटो और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तेज होगी। सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों, रिसर्च और डिजाइन में लाखों सीधे-अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। डिफेंस, स्पेस, मिसाइल और साइबर सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाली चिप्स अगर देश में बनेंगी तो सुरक्षा मजबूत होगी। एआई 5G/6G, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डेटा सेंटर और स्मार्ट सिटी सब के लिए सेमीकंडक्टर जरूरी हैं।

-लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं

पैसा दो-गुना कर देंगे, चार-गुना कर देंगे, चक्कर में फंसे तो गए काम से...

अनजाने लिंक पर कभी भी क्लिक मत करो

भारत में इन दिनों सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने जाल में फंसाने का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। तरह-तरह के लुभावने वादे और उपभोक्ताओं को उनके पैसे दोगुने- चार गुने करने का लालच देकर फंसाया जा रहा है। उपभोक्ता भी फौरी लाभ के लिए उनके चपेटे में आ जाता है। ग्रामीण उपभोक्ता के इस अंक में कोशिश की गई है कि उपभोक्ता को इस बारे में सजग किया जाए।

डिजिटल युग का नया जाल

भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट ने देश के गांव-गांव तक सोशल मीडिया को पहुंचा दिया है। फेसबुक, व्हाट्स अप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म अब केवल संवाद के माध्यम नहीं रहे, बल्कि व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन और सूचना के प्रमुख साधन बन चुके हैं।

लेकिन इस डिजिटल क्रांति के साथ एक खतरनाक प्रवृत्ति भी बढ़ी है, सोशल मीडिया पर फर्जी स्कीमों और ऑनलाइन ठगी का जाल। इन स्कीमों के माध्यम से भोले-भाले उपभोक्ताओं को लाखों-करोड़ों रुपये का चूना लगाया जा रहा है। कभी सरकारी योजना का लाभ के नाम पर, कभी घर बैठे कमाई के बहाने, तो कभी लॉटरी जीतने के झांसे में लोग फंस रहे हैं।

ऐसे समय में उपभोक्ताओं को जागरूक करना और उन्हें फर्जी स्कीमों से सावधान करना अत्यंत आवश्यक है।

फर्जी स्कीमों के प्रकार

भारत में सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी योजनाओं को मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है :

सरकारी योजना के नाम पर ठगी

कई फर्जी पोस्ट्स में दावा किया जाता है कि केंद्र या राज्य सरकार नई योजना लेकर आई है, जैसे कि कोई बताएगा,

- प्रधानमंत्री 5,000 रुपये प्रतिमाह दे रहे हैं।
- महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन दी जा रही है।
- सरकार हर नागरिक को 25 लाख रुपये दे रही है।

> **▶ मोबाइल पर खूब आती हैं फर्जी स्कीमें, सतर्क रहना**
> **▶ ज्यादा ललचाने की जरूरत नहीं, लालच बुरी बला है**

इन संदेशों में अक्सर एक लिंक दिया जाता है, जहां व्यक्तिगत जानकारी (आधार नंबर, बैंक डिटेल्स, ओटीपी) मांगी जाती है। लोग सरकारी लाभ समझकर जानकारी भर देते हैं और उनके बैंक खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं।

घर बैठे कमाई / वर्क फ्रॉम होम स्कीम

प्रतिदिन 5,000 रुपये कमाएं, यूट्यूब वीडियो लाइक कर पैसे पाएं, टेलीग्राम जॉइन कर निवेश को दोगुना करें, ये सब आम झांसे हैं। शुरुआत में कुछ छोटी रकम वापस देकर विश्वास जीत लिया जाता है, फिर बड़ी रकम निवेश करवाकर ठग फरार हो जाते हैं।

फर्जी निवेश और क्रिप्टो स्कीम

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या नकली प्रोफाइल बनाकर लोगों को शेयर मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के लिए उकसाया जाता है। "100% गारंटीड रिटर्न' जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लालच पैदा किया जाता है।

लॉटरी और इनाम का झांसा

आपने 25 लाख की लॉटरी जीती है, आपका मोबाइल नंबर चुना गया है, ऐसे संदेशों में पहले प्रोसेसिंग फीस मांगी जाती है, फिर संपर्क बंद हो जाता है।

फर्जी ई-कॉमर्स ऑफर

सोशल मीडिया पर ब्रांडेड सामान 80-90 प्रतिशत छूट पर दिखाया जाता है। भुगतान करने के बाद या तो सामान नहीं आता या नकली उत्पाद मिलता है।

नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी

फर्जी भर्ती विज्ञापन, सरकारी नौकरी का वादा, रेलवे या बैंक में नियुक्ति, इन सबके नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है।

कैसे फंस जाते हैं लोग?

लालच और त्वरित लाभ की चाह

कम समय में अधिक कमाई का लालच इस मकड़जाल में फंसने का सबसे बड़ा कारण है।

डिजिटल साक्षरता की कमी

ग्रामीण और बुजुर्ग आबादी को तकनीकी जोखिमों की जानकारी कम होती है और इसी

कारण से बहुत से लोग इस झांसे के शिकार हो जाते हैं।

सरकारी योजनाओं की जटिलता

हमारे देश में विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्कीमों में इतनी औपचारिक जटिलताएं होती हैं कि लोगों के लिए असली और नकली योजनाओं में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण बहुत से लोग फर्जी लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं।

विश्वसनीयता का भ्रम

जब कोई लिंक व्हाट्स अप ग्रुप या परिचित के माध्यम से आता है तो लोग उसे सही मान लेते हैं।

सोशल इंजीनियरिंग तकनीक

ठग भावनात्मक दबाव, डर या उत्साह पैदा कर निर्णय लेने का समय नहीं देते।

कानूनी संरक्षण एवं सरकारी प्रयास

भारत में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कई कानूनी प्रावधान मौजूद हैं :

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000**

आईटी एक्ट के तहत ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध दंडनीय हैं।

- **भारतीय दंड संहिता (IPC)**

धोखाधड़ी (धारा 420), जालसाजी आदि पर सख्त सजा का प्रावधान है।

- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019**

भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

- **साइबर क्राइम पोर्टल**

सरकार ने (www.cybercrime.gov.in] (http://www. cybercrime.gov.in) पोर्टल शुरू किया है जहां ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।

- **1930 हेल्पलाइन**

यदि ऑनलाइन ठगी हुई हो तो तुरंत 1930 पर कॉल कर बैंक ट्रांजेक्शन रोकने का प्रयास किया जा सकता है।

- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी**

फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी विज्ञापनों की भरमार है। इन कंपनियों को चाहिए कि, विज्ञापनों की सख्त जांच करें, संदिग्ध अकाउंट तुरंत ब्लॉक करें, उपभोक्ताओं को चेतावनी संदेश दिखाएं एवं स्थानीय भाषा में साइबर सुरक्षा जागरूकता का अभियान चलाएं।

उपभोक्ता क्या सावधानियां बरतें?

- **बहुत अच्छा ऑफर पर संदेह करें**

यदि कोई योजना अविश्वसनीय लग रही है, तो संभवत है कि वह फर्जी है।

- **सरकारी वेबसाइट की पुष्टि करें**

किसी भी सरकारी योजना की जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट (जैसे gov.in) से लें।

- **ओटीपी और बैंक डिटेल साझा न करें**

कोई भी सरकारी या बैंक अधिकारी फोन पर ओटीपी नहीं मांगता।

- **लिंक पर क्लिक करने से पहले जांचें**

अज्ञात लिंक या शॉर्ट URL पर क्लिक करने से बचें।

- **सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच करें**

फर्जी अकाउंट में अक्सर कम फॉलोअर्स, नई प्रोफाइल और संदिग्ध कंटेंट होता है।

- **तुरंत शिकायत करें**

देरी करने से पैसा वापस मिलना कठिन हो जाता है।

आंकड़ों में अपराध

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, साइबर अपराधों के मामलों में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े मामलों में हजारों करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि समस्या गंभीर है और इसे केवल कानून से नहीं, बल्कि सामूहिक जागरूकता से ही नियंत्रित किया जा सकता है।

मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका

पत्रकारों, सामाजिक संगठनों और उपभोक्ता मंचों को चाहिए कि वे :

- फर्जी योजनाओं का खुलासा करें।
- पीड़ितों की कहानियां सामने लाएं।
- सरकार पर सख्त कार्रवाई का दबाव बनाएं।
- डिजिटल साक्षरता अभियान चलाएं।

भविष्य की चुनौतियां

पाठकों आपको यह भी समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक तकनीक के बढ़ते उपयोग से फर्जी वीडियो और आवाज बनाना आसान हो गया है। भविष्य में ठगी और अधिक जटिल हो सकती है। इसलिए तकनीकी सुरक्षा उपायों, जैसे दो-स्तरीय प्रमाणीकरण, साइबर मॉनिटरिंग और एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली को मजबूत करना होगा। सोशल मीडिया पर फर्जी स्कीमों का जाल एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौती बन चुका है। यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि लोगों के विश्वास को भी तोड़ता है। सरकार, सोशल मीडिया कंपनियां, मीडिया और नागरिक समाज—सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस खतरे से निपटें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्वयं उपभोक्ता की है। याद रखें, लालच, जल्दबाजी और अनजाने लिंक पर भरोसा ही ठगी की पहली सीढ़ी है। यदि हम सतर्क रहें, जानकारी की पुष्टि करें और समय रहते शिकायत करें, तो फर्जी स्कीमों के जाल से खुद को और समाज को सुरक्षित रख सकते हैं।

fssai

Eat Right India

Healthy. Safe. Fortified.

Led by FSSAI under the Ministry of Health and Family Welfare

Combat Food Adulteration

DART Book: check food adulterants at home

Food Safety on Wheels: Mobile food-testing lab

100+ tests of food adulterants for schoolchildren

275+ notified labs for all tests

www.fssai.gov.in

आशीष मिश्र

हंगामा है क्यों बरपा, मी लॉर्ड...?

NCERT की किताब में न्यायिक भ्रष्टाचार पर उठे सवाल

NCERT की किताबों के कंटेंट को लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं लेकिन इस बार मामला न्यायिक सिस्टम से जुड़ा है। कक्षा 8 की एक किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात कही गई है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने इस बर एतराज जताते हुए कहा कि, किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम नहीं करने नहीं दिया जाएगा।

क्या हुआ अदालत में?

सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार, 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार" चैप्टर वाली NCERT के 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब बैन कर दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने किताब छापने और बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि जो किताबें छप चुकी हैं, उन्हें जब्त कीजिए और डिजिटल कॉपियों को भी हटाइए। कोर्ट ने इस मामले में NCERT डायरेक्टर और केंद्रीय शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिलेबस से जुड़ी बैठकों की कार्यवाही और विवादित चैप्टर लिखने वाले लेखकों के नाम और उनकी योग्यता बताने को भी कहा गया है। प्रश्न यह है कि, न्यायपालिक में भ्रष्टाचार के सवाल पर देश की सुप्रीम अदालत इतनी तल्ख क्यों है? क्या उसे नहीं पता कि एनसीआरटी की किताबों में बहुत से ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनके पीछे ठोस तथ्यों का अभाव रहा है, लेकिन है तो है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, यह न्यायपालिका को बदनाम करने की गहरी और सोची-समझी साजिश लगती है। जिम्मेदारों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गहराई से जांच होगी और केस बंद नहीं होगा। NCERT पर अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है।

सरकार का पक्ष

सुप्रीम कोर्ट की तल्खी के बाद कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने इस मामले में जिम्मेदारी तय करने और कार्रवाई करने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विवादित चैप्टर को तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और उसका अपमान करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

हालांकि, इस प्रकरण के उठने के बाद NCERT ने माफी मांग ली थी लेकिन सरकारी सूत्रों ने कहा कि, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित आंकड़े संसदीय अभिलेखों और नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड में मौजूद हैं। सरकारी सूत्रों ने स्वीकार किया कि, फैक्ट्स के क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए केंद्र से परामर्श नहीं लिया गया था।

> ▶ सुप्रीम अदालत की बेंच ने जाहिर की नाराजगी
> ▶ सवाल ये कि क्या न्यायिक भ्रष्टाचार विमर्श से परे है

सोशल साइंस टेक्स्टबुक में ज्यूडीशियरी में करप्शन पर चैप्टर

NCERT ने 23 फरवरी को जारी नई टेक्स्ट बुक 'एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2" में 'द रोल ऑफ द ज्यूडीशियरी इन आवर सोसायटी" टॉपिक के अंदर ज्यूडिशियरी में करप्शन का टॉपिक जोड़ा है। इसका पहला पार्ट जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था। ये किताब एकेडमिक सेशन 2026-27 से स्कूलों में पढ़ाई जानी है।

सोशल साइंस की इस किताब में लिखा गया है- 'Justice delayed is justice denied", यानी इंसाफ में देरी नाइंसाफी की तरह है। यहां सुप्रीम कोर्ट में 81 हजार, हाईकोर्ट्स में 62 लाख 40 हजार, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के 4 करोड़ 70 लाख पेंडिंग केस की संख्या भी बताई गई है।

किताब में ज्यूडीशियरी से जुड़े अहम पॉइंट्स

- इसमें कोर्ट की हायरार्की और न्याय तक पहुंच को समझाने से ज्यादा ज्यूडिशियल सिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे करप्शन और केस बैकलॉग को बताया गया है।
- करप्शन वाले सेक्शन में बताया गया है कि जज एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं जो न केवल कोर्ट में बल्कि कोर्ट के बाहर भी उनके व्यवहार को कंट्रोल करता है।
- ज्यूडिशियरी के अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को भी समझाया गया है। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CPGRAMS) के जरिए शिकायतें लेने के तय तरीके भी बताए गए हैं।
- किताब के मुताबिक CPGRAMS सिस्टम के जरिए 2017 और 2021 के बीच 1,600 ज्यादा शिकायतें मिली थीं।
- किताब में गंभीर मामलों में जजों को हटाने के संवैधानिक नियम के बारे में भी बताया गया है कि पार्लियामेंट इंपीचमेंट मोशन पास करके जज को हटा सकती है।
- बच्चे पढ़ेंगे कि ऐसे मोशन पर सही जांच के बाद ही विचार किया जाता है। इस दौरान जज को मामले में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है।
- चैप्टर में लिखा है- लोग ज्यूडिशियरी के अलग-अलग लेवल पर करप्शन का सामना करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की न्याय तक पहुंच की समस्या और बिगड़ सकती है।
- यह भी बताया है कि राज्य और केंद्र ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और करप्शन के मामलों के खिलाफ फास्ट एक्शन लेना शामिल है।

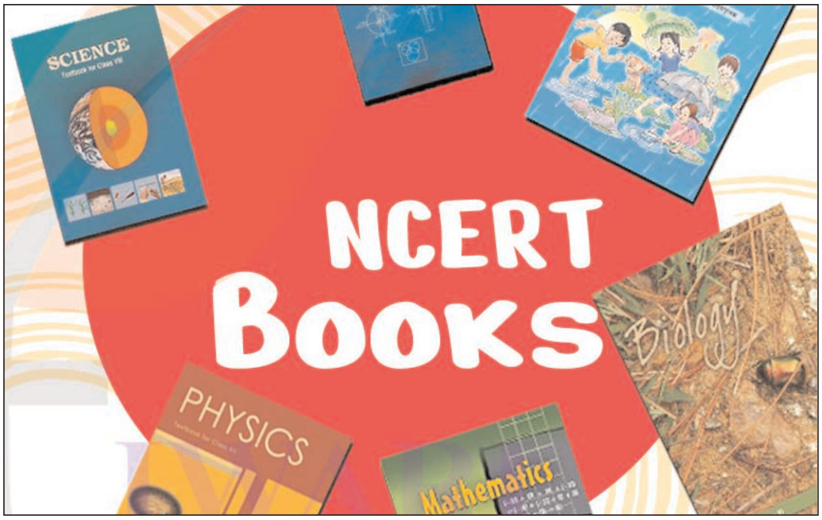

CJI ने कड़ी आपत्ति जताई थी

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने CJI सूर्यकांत, जस्टिस विपुल एम पंचोली और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच में यह मामला उठाया था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि, 'मुझे इसकी पूरी जानकारी है। यह पूरे ज्यूडीशियल इंस्टीट्यूशन के लिए चिंता की बात है। यह सोचा-समझा कदम लग रहा है। मैं किसी को भी, चाहे वे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हों, इंस्टीट्यूशन को बदनाम नहीं करने दूंगा। मैं इस मामले पर खुद नोटिस ले रहा हूं।'

NCERT ने माफी मांगी

सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद NCERT ने कहा कि वे ज्यूडिशियरी का बहुत सम्मान करते हैं। किताब में गलती अनजाने में हुई है और NCERT को उस चैप्टर में गलत मटेरियल शामिल करने का अफसोस है। चैप्टर को दोबारा लिखा जाएगा।

एनसीईआरटी ने कोर्ट को बताया कि किताब 24 फरवरी को रिलीज हुई थी। इसकी 2.25 लाख कॉपियां छपी हैं। 38 बिक चुकी हैं, बाकी इन्वेंट्री में हैं। बिकी कॉपियां जल्द रिकवर कर लेंगे।

दो समितियां तय करती हैं, किताबों में क्या जाएगा ?

NCERT की किताबें कोई एक लेखक नहीं, बल्कि समितियां तय करती हैं। जिस किताब पर विवाद है, उसे दो समितियों ने तैयार किया है।

- कॅरिकुलर एरिया ग्रुपः आईआईटी गांधीनगर में गेस्ट प्रोफेसर मिशेल डैनिनो की अध्यक्षता वाली यह समिति सामाजिक विज्ञान के लिए बनी है, जो सामग्री के

चयन, लेखन की देखरेख करती है।

- नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग-लर्निंग मटेरियल कमेटीः यह हाईलेवल कमेटी है, जिसने किताब को फाइनल किया है। इसके अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर एमसी पंत हैं। मंजुल भार्गव सह अध्यक्ष (प्रिंसटन विवि के प्रोफेसर), सुधा मूर्ति (सांसद), संजीव सान्याल (पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य) समेत 19 सदस्य हैं।
- पिछले साल डैनिनो पर मुगल काल के इतिहास को पाठ्यक्रमों में कम करने का आरोप लगा था।

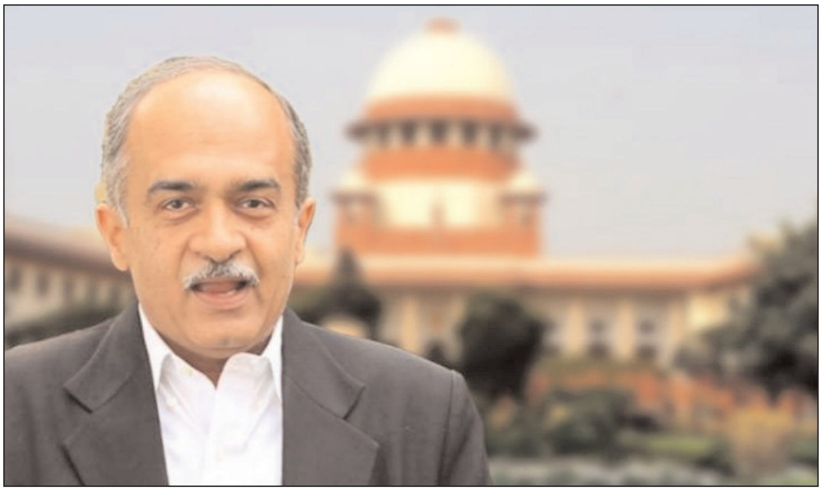

भ्रष्टाचार समस्या

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इसी महीने जारी रिपोर्ट के मुताबिक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 182 देशों के बीच भारत की रैंक 91 है। पिछले साल के मुकाबले देश ने 5 अंकों का सुधार जरूर किया, लेकिन भ्रष्टाचार अब भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसकी वजह से तमाम सरकारी योजनाएं और नीतियां अपना असर खो देते हैं और आम लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जब बात जूडिशरी की आती है, तो भावनाएं बदल जाती हैं।

जस्टिस वर्मा केस

देश में न्यायपालिका उन चंद संस्थाओं में है, जिस पर लोग आज भी पूरा भरोसा करते हैं। जब तमाम उम्मीदें कमजोर हो जाती हैं, तब अदालतों से आस जगती है। लेकिन, इस भरोसे की कुछ कीमत भी है और वह है पारदर्शिता व जवाबदेही। कोई भी सिस्टम करप्ट नहीं होता, उसे चलाने वाले चंद लोग ही होते हैं। देश की न्यायिक व्यवस्था को भी इस मामले में कुछ सवाल झेलने पड़े हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के करप्शन का मामला पिछले साल मार्च का है और अभी तक यह अंजाम तक नहीं पहुंचा है। इसी तरह, दिसंबर में ही सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी कि करियर के आखिरी में बड़े फैसले देने का ट्रेंड बढ़ रहा है। जरूरी नहीं कि करप्शन पैसों का ही हो।

लंबित मामले

अदालतें भरोसे का नाम हैं, पर यह भी सच है कि आम आदमी अदालतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मुकदमे सालों-साल चलते हैं और खर्चीले हैं। विभिन्न अदालतों में लगभग 4.9 करोड़ केस पेंडिंग हैं। जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक - न्यायाधीशों के तमाम पद खाली हैं, जिससे न्याय की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है।

अच्छी पहल

भारतीय न्यायपालिका की इस मायने में तारीफ होनी चाहिए कि पारदर्शिता के लिए वह खुद पहल करती है। मसलन, पिछले साल मई में शीर्ष अदालत के न्यायधीशों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने पर सहमति जताई थी। इस कदम ने न्यायपालिका की गरिमा को और बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट को फिर उसी तरह की पहल करते हुए कोई रास्ता निकालना चाहिए।

प्रशांत भूषण के सवाल

इंडियन एक्सप्रेस में छपे अपने लेख में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एक बार फिर से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के सवाल को उठाया है। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2007 में कराए गए सर्वे का जिक्र किया जिसमें भारत में 77 प्रतिशत लोग यह मानते हैं कि न्यायिक व्यवस्था में भष्टाचार है। उन्होंने कहा है कि, हमें न्यायिक भ्रष्टाचार पर चर्चा करने की जरूरत है। उन्होने सुझाव दिया कि, न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन और अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाना चाहिए। कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में बदलाव की जरूरत है। स्कैंडलाइजिंग कोर्ट प्रावधान हटे। कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग बढ़े, सील्ड कवर रिपोर्ट बंद की जाए जैसा कि राफेल, जज लोया जैसे मामलों में हुआ।

-लेखक ग्रामीण उपभोक्ता के संपादकीय निदेशक हैं

आलोक सांडिल्य

बिना डॉक्टर से पूछे मत खाना एंटीबायोटिक...

भारत में बिना जाने-समझे दवा खाने का खतरनाक चलन

भारत में एंटी बायोटिक दवाओं के इस्तेमाल का चलन बढ़ता जा रहा है। आम उपभोक्ता ऐसी दवाओं का सेहत पर क्या असर पड़ता है इसे लेकर बहुत जागरूक नहीं होता है। आम सर्दी, खांसी या बुखार होने पर देश के अधिकतर लोग तो केमिस्ट से ही दवा पूछ कर खा लेते हैं। कोई आज छोटा-मोटा दर्द, बुखार या जुकाम हो जाए तो धड़ल्ले से एंटीबायटिक दवाओं का इस्तेमाल करने लगता है। यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।

उपभोक्ताओं, आपको शायद याद होगा कुछ साल पहले सूरत में प्लेग फैला था। देश भर में कोहराम मच गया था। प्लेग के इलाज के लिए ट्रेट्रासाइक्लीन एंटीबायोटिक को प्रभावी बताया गया। देखते-देखते देश भर में ट्रेट्रासाइक्लीन का स्टॉक खत्म हो गया। अमेरिका से दवा मंगानी पड़ी और अमेरिका के पास पहले से स्टॉक ट्रेट्रासाइक्लीन की पूरी खपत हो गई।

अब इस प्लेग और ट्रेट्रासाइक्लीन के पीछे की असली कहानी को जानिए। अमेरिका में ट्रेट्रासाइक्लीन का उत्पादन बहुतायत में किया जाता था। अमेरिकी ड्रग कंट्रोल फेडरेशन ने ट्रेट्रासाइक्लीन को जन स्वास्थ्य के लिए घातक बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया। बस कहानी यहीं से शुरू होती है। ट्रेट्रासाइक्लीन का भारी स्टॉक अमेरिका में पड़ा था। अब उसकी खपत कहां हो, यह एक बड़ा सवाल था। सूरत में अचानक प्लेग फैला और ट्रेट्रासाइक्लीन का सारा स्टॉक खत्म।

प्लेग को खत्म करने में ट्रेट्रासाइक्लीन कितनी प्रभावी रही इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला लेकिन यह सही है इस बहाने वह दवा पूरी खप गई। अब इस प्लेग के शुरू होने और खत्म होने के गणित में ट्रेट्रासाइक्लीन नाम के इस एंटीबायोटिक के पीछे दुनिया भर में फैले दवा कारोबारियों की भी क्या कोई भूमिका थी यह सवाव तब भी था और आज भी है।

बहरहाल, आज दूध का दूध पानी का पानी कॉलम मे हम एंटीबायोटिक के अंधाधुंध इस्तेमाल और उससे होने वाले सेहत को नुकसानके मसले पर चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया विशेषकर गरीब देशों में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को लेकर कहानी काफी कुछ एक जैसी है। फौरी आराम के लिए मरीज को धड़ल्ले से एंटीबायोटिक दवाएं खिला दी जाती हैं।

▶ एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से हो जाती है गंभीर बीमारियां

▶ डॉक्टर की सलाह पर ही खाएं ये दवाएं

भारत में एंटी बायोटिक दवाओं के इस्तेमाल का चलन बढ़ता जा रहा है। आम उपभोक्ता ऐसी दवाओं का सेहत पर क्या असर पड़ता है इसे लेकर बहुत जागरूक नहीं होता है। आम सर्दी, खांसी या बुखार होने पर देश के अधिकतर लोग तो केमिस्ट से ही दवा पूछ कर खा लेते हैं। कोई आज छोटा-मोटा दर्द, बुखार या जुकाम हो जाए तो धड़ल्ले से एंटीबायटिक दवाओं का इस्तेमाल करने लगता है। यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।

एंटीबायोटिक क्या काम करता है?

एंटीबायोटिक का मुख्य रूप से काम यह है कि बुरे बैक्टीरिया या जिसकी वजह से शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है, उसे नष्ट करना । शुरुआत में तो यह दवा कारगर होती है लेकिन इसके निरंतर उपयोग से बुरे बैक्टरियों में इससे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और यह दवाई असर करना कम कर देती है। इसके बाद, आपके डॉक्टर या केमिस्ट दवाइयों (एंटीबायोटिक) की डोज और पावर बढ़ा कर देने लगते है। इससे स्वास्थ्य और बिगड़ने की

दूध का दूध, पानी का पानी

स्थिति में पहुंच जाता है।

एंटीबायोटिक के प्रकार

माना जाता है की सबसे पहले एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग 1942 में सेलमैन वाक्समैन द्वारा किया गया था। बाजार में मुख्यतः तीन प्रकार की एंटीबायोटिक दवाईयां उपलब्ध हैं- प्राकृतिक, सिंथेटिक और सेमीसिंथेटिक। इन्हें बनाने में इस्तेमाल की गई चीजों से इनका प्रकार निर्धारित किया जाता है। जो एंटीबायोटिक प्राकृतिक (नेचुरल) पदार्थों से मिलकर बनती है उसे हम प्राकृतिक एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। जो पूरी तरह से कृत्रिम रूप से बनाई जाती है उसे सिंथेटिक एंटीबायोटिक की श्रेणी में रखा जाता है एवं जिसका निर्माण प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों पदार्थों से मिलकर बनता है उसे सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक श्रेणी में गिना जाता है। प्राकृतिक एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पादन अमीनोग्लाइकोसाइड जैसे जीवित जीवों के जरिये होता है और अन्य एंटीबायोटिक कृत्रिम तरीकों, जैसे सल्फोनामाइड्स, क्वीनोलोंस और ऑक्साजोलाइडिनोंस से बनाये जाते हैं।

एंटीबायोटिक्स के कुछ अन्य प्रकार

- **पेनिसिलिन समूह:** यह एंटीबायोटिक दवा बीटा-लैक्टम का एक समूह है जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को नष्ट करने काम करती हैं।
- **सेफालोस्पोरिन:** यह दवा जीवाणुनाशक का एक विस्तृत समूह है, जो त्वचा, श्वास- तंत्र और हड्डियों के संक्रमण से बचने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **मैक्रोलाइड:** यह दवा बैक्टीरिया के प्रोटीन संश्लेषण को रोककर उनके विकास को रोकता है। इनका उपयोग निमोनिया, साइनसाइटिस, गले, और श्वास- तंत्र के संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है।
- **ट्रेट्रासाइक्लीन:** यह एंटीबायोटिक दवा व्यापक-स्पेक्ट्रम का एक समूह है, जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। कई बैक्टीरियल बीमारियों के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है।
- **फ्लुओरोक्विनोलोन:** यह शक्तिशाली ब्रॉड-स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं, इसका उपयोग गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण जैसे निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI), और पेट के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है।

हर एंटीबायोटिक दवा का असर अलग प्रकार के बैक्टीरिया पर होता है।

लाभदायक या नुकसानदेह

- लगातार इसके गलत उपयोग से सामान्य (अन्य) दवाएं असर करना बंद कर देती हैं।
- बिना परामर्श के या हाई डोज का सेवन करने से आपको एलर्जी, दस्त, लीवर और किडनी की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है।
- जैसा की हमने जाना की एंटीबायोटिक का ज़्यादा सेवन, शरीर की प्राकृतिक रोग-प्रतिरोधक क्षमता को कम कर सकती है।
- हाँ, अगर सही तरीके से और सही बीमारी में एंटीबायोटिक ली जाए तो यह जीवन रक्षक का भी काम करती है।

भारत में स्थिति

भारत पूरे विश्व-भर में, एंटीबायोटिक का सबसे अधिक उपयोग करने वाले देशों में से एक है। कई बार लोकल मेडिकल स्टोर बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दवा दे देते हैं, जो स्वास्थ्य के नजरिए से ठीक नहीं है। ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी जानकारी होते हुए भी लोग इसका उपयोग धड़ल्ले से करते हैं।

आप जो गलतियां करते हैं

- डॉक्टर की पूरी बात न सुनना
- गूगल पर देखकर दवा लेना
- 3-4 दिन में ठीक लगने पर दवा बंद कर देना
- बची हुई पुरानी दवा दोबारा उपयोग करना
- बच्चों को खुद से दवा दे देना

उपभोक्ताओं के लिए सुझाव

- सबसे जरूरी बात ध्यान रखने योग्य यह है की, डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक दवा न लें।
- अगर आप किसी भी दवाई का सेवन कर रहे हैं तो पूरा कोर्स जरूर ख़त्म करें।

- आमतौर पर वायरल बीमारी में सिर्फ़ एंटीबायोटिक का सेवन न करें। डॉक्टर से परामर्श जरूर लें ।
- घर में बची हुई या पुरानी दवा का बिना समझे फिर से उपयोग न करें।
- जो दवा आप ले रहे हैं उसके बारे में अपने परिवार वालों को जरूर बतायें।

इसमें कोई दोराय नहीं कि मेडिकल साइंस के क्षेत्र में एंटीबायोटिक आज के दौर की सबसे बड़ी खोज है, लेकिन इसका बिना परामर्श के उपयोग हमारे लिए संकट बन सकता है। दवा तभी तक दवा है, जब तक उसका सही उपयोग हो, अन्यथा वही दवा बीमारी की वजह भी बन सकती है।

-लेखक ग्रामीण उपभोक्ता के संवाददाता हैं

सुरेश उपाध्याय

‘ईको एंजाइटी’ ने कैसे दी ग्रेटा थनबर्ग के सवालों को नई धार...?

क्लाइमेट चेंज ने युवाओं पर सबसे गहरा असर डाला

स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने कुछ वर्षों पहले दुनिया के सामने पर्यावरण को लेकर कई सवाल उठाए। उन सवालों में एक सवाल यह भी था कि हम भावी पीढ़ी के लिए किस तरह की दुनिया को छोड़ कर जाएंगे। उनकी चिंताओं में पर्यावरण, कृषि, ऊर्जा एवं सदाजीवी विकास के मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए। उनकी चिताओ में सबसे प्रमुख था वातावरण में बदलाव और उसका मौजूदा समाज पर असर। अब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने ग्रेटा थनबर्ग की चिताओं को और गहरा कर दिया है।

दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का असर लोगों की कार्यशैली पर पड़ रहा है। इस बदलाव के कारण खासतौर पर युवाओं में चिंता, बेबसी और डर की भावनाएं प्रबल हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के चलते युवाओं में ईको एंजाइटी यानी वातावरण में बदलाव से पनपे मर्ज के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि, दुनिया भार के करीब 90 फीसदी युवाओं ने जलवायु परिवर्तन को महसूस किया है और करीब 70 प्रतिशत ने इसके कारण अपने जीवन पर स्थायी प्रभाव को माना है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम (यूएनईपी) ने 2024 में जब 'नेविगेटिंग न्यू होराइजंसः ए ग्लोबल फोरसाइट रिपोर्ट ऑन प्लेनेटरी हेल्थ एंड ह्यूमन वेलबीइंग' रिपोर्ट जारी की, तब यह भी चेताया कि दुनिया भर में युवाओं के बीच ईको एंजायटी नाम का संकट तेजी से उभर रहा है। इसे क्लाइमेट ग्रीफ अथवा जलवायु से संबंधित दुख के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। यह नकारात्मक भाव ना पर्यावरण के क्षरण और जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले खतरों की उपज है। यूएनईपी की रिपोर्ट ने युवाओं में क्लाइमेट एंजायटी यानी जलवायु से जुड़ी चिंता को सबकी नजरों के सामने मौजूद संकट बताया और यह भी चेताया कि यह आने वाली पीढ़ियों पर थोपी जा रही एक भावनात्मक तबाही है।

पत्रिका डाउन टू अर्थ ने इस दिशा में पहल करते हुए 2025 में 16 से 25 वर्ष के आयु वर्ग यानी 21वीं सदी की पहली पीढ़ी के 300 से अधिक लोगों के बीच एक जनमत सर्वेक्षण

कराया। जनमत सर्वेक्षण के निष्कर्षों से जाहिर होता है कि ईको एंजायटी कितनी गहराई तक जड़ जमा चुकी है। लगभग 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अपने आसपास जलवायु में बदलाव महसूस कर रहे हैं जबकि 67 प्रतिशत ने कहा कि ये बदलाव उनके रोजमर्रा के जीवन और जीवनशैली को पहले ही प्रभावित कर चुका है।

पूरी पीढ़ी को सामान्य जलवायु का आभास ही नहीं

जलवायु परिवर्तनों पर नजर रखने वाले अध्ययनों से संकेत मिलता है कि पिछले 25 वर्षों में जन्मी पीढ़ी ने शायद कभी सामान्य जलवायु का अनुभव ही नहीं किया। हीटवेव से लेकर चक्रवातों और बाढ़ तक धरती की हलचल बदल चुकी है। युवा इसे पहले से कहीं अधिक तेजी से महसूस कर रहे हैं। ज्यूरिच के इंस्टीट्यूट फॉर एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट साइंस में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं संयुक्त राष्ट्र के जलवायु विज्ञान विश्लेषण के प्रमुख लेखक इरिश फिशर के अनुसार, मौजूदा समय में जलवायु स्टेरॉयड पर रहने वाले खिलाड़ी जैसा रवैया दिखा रही है।

जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्टिंग और शोध करने वाले वैज्ञानिकों व पत्रकारों के

अंतरराष्ट्रीय संगठन क्लाइमेट सेंट्रल के वैज्ञानिकों का कहना है कि फरवरी 1986 में और उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति ने सामान्य तापमान वाला एक भी महीना नहीं देखा है। तब से हर महीना औसत से अधिक गर्म रहा है।

बदलाव की कड़ियां

युवा आखिर जलवायु परिवर्तन की कड़ियों को किन बदलावों से जोड़ते हैं? जनमत सर्वेक्षण में ऐसे नौ लक्षण सूचीबद्ध किए गए थे। युवा असमय मौसम से लेकर बढ़ते तापमान और कीट-पतंगों की बढ़ोतरी जैसे एक से अधिक विकल्प चुन सकते थे। दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने जलवायु परिवर्तन को अधिक तापमान और असमय गर्मी या वर्षा से जोड़ा। लगभग 40 प्रतिशत ने इसे धुंधले या कोहरे भरे दिनों से जोड़ा, जबकि 36 प्रतिशत ने खाद्य गुणवत्ता में बदलाव को जलवायु परिवर्तन की एक बानगी बताया। 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अत्यधिक ठंड को भी जलवायु परिवर्तन का लक्षण माना और 32 प्रतिशत ने कीट-पतंगों में वृद्धि को इससे जोड़ा।

सभी वर्गों पर समान असर

उनके सामने एक सवाल यह था कि क्या जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विभिन्न आर्थिक वर्गों पर अलग-अलग पड़ता है? इसके उत्तर में 61 प्रतिशत ने कहा कि इसका असर समाज के सभी वर्गों-अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग पर समान रूप से पड़ता है। हालांकि, जो लोग असमान प्रभाव मानते थे, उनमें स्पष्ट सहमति थी कि सबसे अधिक नुकसान गरीबों को होता है।लैंगिक दृष्टि से राय अधिक एकरूप रही। करीब 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करता है।

युवाओं पर इन चिंताओं का भावनात्मक बोझ स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। उत्तरदाताओं से जलवायु परिवर्तन को लेकर अपनी भावनाएं छह विकल्पों में से चुनने को कहा गया। ये विकल्प थे डरा हुआ और उदास, चिंतित, गुस्सा, असहाय, ठगे हुए और उदासीन। उन्हें एक से अधिक विकल्प चुनने की अनुमति थी। सभी भावनाओं को व्यापक समर्थन मिला, जो जलवायु चिंता की गहराई को दर्शाता है। 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने खुद को चिंतित, 54 प्रतिशत न बेबस और 43 प्रतिशत ने डरा हुआ और उदास बताया। कई लोगों ने गुस्सा और ठगे जाने की भावना भी जाहिर की।

भविष्य को लेकर भय

दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का असर लोगों की कार्यशैली पर पड़ रहा है। इस बदलाव के कारण खासतौर पर युवाओं में चिंता, बेबसी और डर की भावनाएं प्रबल हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के चलते युवाओं में ईको एंजाइटी यानी वातावरण में बदलाव से पनपे मर्ज के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि, दुनिया भर के करीब 90 फीसदी युवाओं ने जलवायु परिवर्तन को महसूस किया है और करीब 70 प्रतिशत ने इसके कारण अपने जीवन पर स्थायी प्रभाव को माना है।

युवाओं में भविष्य को लेकर डर बना हुआ है। लगभग 53 प्रतिशत को आशंका है कि जलवायु परिवर्तन से बीमारियां बढ़ेंगी, एक-तिहाई से अधिक ने खाद्य कमी की आशंका जताई और 45 प्रतिशत को जल संकट का डर है। 94 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। आधे लोगों ने इस मुद्दे पर सरकारी कार्रवाई को निराशाजनक बताया।

कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि ऐसी प्रतिक्रियाएं पूरी तरह तर्कसंगत हैं। क्लाइमेट एंजायटी पर एक बड़े अध्ययन की सह लेखिका और बाथ विश्वविद्यालय से जुड़ीं कैरोलिन हिकमैन के अनुसार, हमारे बच्चों की चिंता पूरी तरह जायज है, क्योंकि वे सरकारों की ओर से जलवायु परिवर्तन पर अपर्याप्त प्रतिक्रिया देख रहे हैं। उनके अनुसार, बच्चे और युवा दुनिया भर में संगठित हो रहे हैं और सरकारों को अदालत में ले जा रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई न करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

रास्ता क्या है?

अब सवाल यह है कि, युवा पीढ़ी के पास रास्ता क्या है? अधिकतर विशेषज्ञ इसके जवाब में लाचारी ही जाहिर करते हैं। उनकी स्पष्ट राय है कि समाधान का रास्ता सिर्फ विकास को सदाजीविता पैमाने पर कस कर ही हम इस प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। हरित ऊर्जा के उत्पादन और कृषि की मौजूदा शैली में बदलाव भी वातावरण में बदलाव की प्रक्रिया को धीमा कर सकती कर सकती है।

-लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं

डी.के. दुबे

उपभोक्ता अदालत की अनदेखी पड़ी भारी प्रोजेक्ट की कमान बिल्डर से छीन D.M. को सौंपी

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का ऐतिहासिक फैसला

घर खरीदारों को वर्षों तक फ्लैट या प्लॉट का इंतजार कराना और फिर रिफंड देने से इनकार करना अब बिल्डरों को भारी पड़ सकता है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने एक अहम फैसले में ग्रेटर नोएडा के सुशांत मेगापोलिस प्रोजेक्ट की कमान बिल्डर से छीनकर गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को सौंपने का आदेश दिया है। यह प्रोजेक्ट अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड का हिस्सा है। यह फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि पहली बार किसी उपभोक्ता अदालत ने सीधे जिला प्रशासन को किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का प्रशासन संभालने का निर्देश दिया है।

पांच साल पुराना आदेश बिल्डर ने नहीं माना

NCDRC को यह सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि बिल्डर ने पांच साल पहले दिए गए रिफंड आदेश को आज तक लागू नहीं किया। मामला उन खरीदारों से जुड़ा है जिन्होंने 2008 में रेजिडेंशियल प्लॉट बुक किए थे, लेकिन 12-13 साल बीत जाने के बाद भी न तो प्लॉट मिले और न ही पैसे वापस किए गए। इतना ही नहीं, जब खरीदारों ने प्रोजेक्ट पर रिसीवर (Receiver) नियुक्त करने की मांग की, तो बिल्डर ने उस याचिका पर भी कोई जवाब दाखिल नहीं किया।

NCDRC का सख्त फैसला

जस्टिस सुदीप अहलूवालिया और साधना शंकर की पीठ ने कहा, न्याय के लिए यह जरूरी है कि जजमेंट डेब्टर कंपनी की संपत्तियों, विशेष रूप से 'सुशांत मेगापोलिस" प्रोजेक्ट का नियंत्रण रिसीवर को सौंपा जाए। साथ ही निर्देश दिया कि गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट इस प्रोजेक्ट का प्रशासन संभालेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी नए खरीदार या तीसरे पक्ष से आने वाला भुगतान सीधे बिल्डर को न मिले। सभी भुगतान केवल DM/रिसीवर के माध्यम से हों। कंपनी की कोई भी चल संपत्ति या शेयर किसी तीसरे पक्ष को ट्रांसफर न किए जाएं।

पांच सितारा होटल को निजता भंग करने पर हर्जाना भरने का आदेश

जिला उपभोक्ता अदालत ने एक अहम फैसले में उदयपुर स्थित फाइव स्टार होटल लीला पैलेस को मेहमान की निजता भंग करने का दोषी ठहराते हुए 10.10 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है।

मामला एक मेहमान से जुड़ा है, जो अपनी पत्नी के साथ होटल में ठहरे थे। परिवाद के अनुसार, होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ ने मास्टर-की का इस्तेमाल कर बिना अनुमति कमरे में प्रवेश किया, जिससे मेहमान की निजता का गंभीर उल्लंघन हुआ। उस समय कमरे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे भी चालू नहीं थे। उपभोक्ता अदालत ने माना कि होटल की आतिथ्य सेवाओं में गंभीर कमी रही। कोर्ट ने होटल को आदेश दिया कि वह कमरे का किराया 55 हजार रुपये ब्याज सहित लौटाए, साथ ही मानसिक पीड़ा और वाद खर्च को मिलाकर कुल 10.10 लाख रुपये का मुआवजा अदा करे। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि होटल प्रबंधन ने बार-बार आश्वासन तो दिए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया। इसे सेवा में कमी और गोपनीयता का उल्लंघन मानते हुए होटल को जिम्मेदार ठहराया गया।

ट्रेन लेट, छात्रा ने ठोंका मुकदमा, अब रेलवे भरेगा हर्जाना

कई बार जिला उपभोक्ता अदालतें भी ऐसे फैसले सुनाती हैं जो बड़ी अदालतों के लिए अनुकरणीय बन जाती हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से रेलवे की लापरवाही और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक मेधावी छात्रा की ट्रेन लेट होने के कारण महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा छूट गई थी, जिसके बाद छात्रा ने हार न मानते हुए रेलवे के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोल दिया। सात साल तक चली इस लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब जिला उपभोक्ता फोरम ने रेलवे को सेवा में बड़ी चूक का दोषी माना है और छात्रा को नौ लाख दस हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश जारी किया है।

क्या है पूरा मामला ?

पूरा मामला मई 2018 का है, जब बस्ती के पिकौरा बक्स मोहल्ले की निवासी समृद्धि सिंह को लखनऊ के जयनारायण पीजी कॉलेज में बीएससी बायोटेक की प्रवेश परीक्षा देनी थी। परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्होंने बस्ती से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन का टिकट लिया था। ट्रेन का लखनऊ पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 11:00 बजे था, जबकि छात्रा को परीक्षा केंद्र पर दोपहर 12:30 बजे तक रिपोर्टिंग करनी थी। पर्याप्त समय हाथ में होने के बावजूद रेलवे की लेटलतीफी ने समृद्धि की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ट्रेन अपने तय समय से करीब ढाई घंटे की देरी से दोपहर 1:34 बजे लखनऊ पहुंची, जिसके चलते समृद्धि का साल भर का परिश्रम और परीक्षा दोनों ही हाथ से निकल गए।

इस मानसिक पीड़ा और शैक्षिक नुकसान से आहत होकर समृद्धि ने इस मामले को उपभोक्ता अदालत में ले जाने का फैसला किया। शुरुआत में रेलवे मंत्रालय, महाप्रबंधक और स्टेशन अधीक्षक को कानूनी नोटिस भेजे गए, लेकिन जब विभाग की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो 11 सितंबर 2018 को उपभोक्ता अदालत में औपचारिक मुकदमा दायर किया गया। सुनवाई के दौरान रेलवे ने यह तो स्वीकार किया कि ट्रेन विलंबित थी, लेकिन वह इस देरी के पीछे कोई भी ठोस या तर्कसंगत कारण पेश करने में पूरी तरह विफल रहा।

उपभोक्ता अदालत का फैसला

जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्रा के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि रेलवे की इस लापरवाही ने न केवल छात्रा का कीमती समय बर्बाद किया, बल्कि उसके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया।

आयोग ने रेलवे को आदेश दिया कि वह आदेश के 45 दिनों के भीतर छात्रा को कुल 9,10,000 रुपये का भुगतान करे। इसके साथ ही यह कड़ा निर्देश भी दिया गया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर यह राशि नहीं दी जाती है, तो रेलवे को संपूर्ण भुगतान राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अलग से चुकाना होगा। यह फैसला उन लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ी जीत है जो अक्सर ट्रेनों की देरी को अपनी नियति मानकर चुप रह जाते हैं।

ग्राहक को हुआ नुकसान, आयोग ने कहा 2 माह में पैसा दो

आधी-अधूरी साड़ी प्रिंटिंग मशीन देने के एक मामले में भदोही जिला उपभोक्ता आयोग ने एर दिलचस्प फैसला सुनाया है। जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन न्यायाधीश ने चेताया कि अगर दो माह में पैसा नहीं दिया जाता है तो पूरी धनराशि 12 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ देनी होगी। कंपनी को 10 हजार रुपए उपभोक्ता को वाद खर्च के रूप में भी देने होंगे।

साड़ी प्रिंटिंग मशीन का पूरा पैसा लेने के बाद भी उपभोक्ता को आधी-अधूरी मशीन देने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने लखनऊ स्थित प्रिंटिंग मशीन की कंपनी को पौने चार लाख रुपए छह फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया। जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन न्यायाधीश संजय कुमार डे ने उपभोक्ता को 10 हजार रुपए वाद खर्च दिए जाने का भी आदेश दिया।

आयोग मे अफने फैसले में कहा कि दो महीने में आदेश का अनुपालन न होने पर पूरी धनराशि को 12 फीसदी ब्याज के साथ देना होगा। सुरियावां के मलेपुर मलाईपुर निवासी सुनील कुमार मिश्र ने 25 जून 2025 को जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत में मे. कलर डेवलपर्स इंडिया के प्रो. आशीष बिसेन रिंग रोड कमला नेहरू नगर लखनऊ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत में बताया गया कि उन्होंने कपड़े की प्रिंटिंग के लिए मशीन खरीदने के लिए कंपनी को कुल तीन लाख 75 हजार रुपए दिए। जिसमें ब्याज पर पैसा लेकर 17 अक्तूबर 2023 को दो लाख व 30 अक्तूबर 2023 को एक लाख रुपए भेजा। वहीं एक मई 2024 को 70 हजार और पांच हजार रुपए नगद ले जाकर कंपनी को दिया। जिसके बाद कंपनी ने उन्हें मशीन तो भेजा, लेकिन उसका प्रिंटिंग हेड नहीं भेजा।

आर्थिक क्षति से परेशान था उपभोक्ता

बताया गया कि कंपनी के इंजीनियर प्रिंटिंग हेड ले जाकर उसे चालू करेंगे। जून 2024 के बाद कई बार कहने के बाद भी कंपनी की ओर से प्रिंटिंग हेड मशीन नहीं भेजी गई। जिससे मशीन चालू नहीं हो सकी। इससे उसे आर्थिक क्षति हुई। जिसके बाद उसने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

उपभोक्ता आयोग की ओर से नोटिस भेजी गई।

इसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे व सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव की पीठ ने उपभोक्ता की सेवा में कमी पाते हुए तीन लाख 75 हजार रुपए दो माह के अंदर छह फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया।

आयोग का फैसला नहीं माना, लग गई लाखों की चपत

रायबरेली में एक बीमा कंपनी को उपभोक्ता आयोग का आदेश न मानना महंगा पड़ गया। आदेश के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में दायर मुकदमा खारिज हो गया। इसके चलते कंपनी को 33 साल का जुर्माना भरना पड़ा। कंपनी ने वादी को 40500 रुपए के बजाय छह लाख 46 हजार का भुगतान किया। उपभोक्ता आयोग ने रिकवरी के मुकदमे में कंपनी से वादी को भुगतान दिलाया।

क्या है पूरा मामला?

शहर के कैपरगंज निवासी महमूद हसन ने 1991 में उपभोक्ता फोरम में दावा दायर किया। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान का 40 हजार रुपए का बीमा था। इसी दौरान दुकान में 19500 रुपए नकदी सहित 75 हजार की घड़ियां चोरी हो गई। केस दर्ज होने के बाद उन्होंने सभी जानकारी बीमा कंपनी को दी। सर्वेयर ने मामले की जांच कर रिपोर्ट बीमा कंपनी को सौंपी। कंपनी ने ग्राहक को 10 हजार छह सौ 79 रुपए का भुगतान किया। वादी ने क्लेम के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में 1991 में वाद दायर किया। उपभोक्ता फोरम ने वादी के अधिवक्ता केपी वर्मा की बहस सुनने के बाद बीमा कंपनी को 60 दिन में 40500 रुपए देने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि समयावधि में भुगतान न करने पर 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। 60 दिन बीतने के बाद भी भुगतान न होने पर वादी के अधिवक्ता ने रिकवरी का मुकदमा उपभोक्ता फोरम में दायर किया।

बीमा कंपनी ने उपभोक्ता फोरम के आदेश के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। इस दौरान उपभोक्ता फोरम में रिकवरी का मुकदमा स्थगित रहा। उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी की सुनवाई के बाद वर्ष 2023 मुकदमा खारिज कर दिया।

दोबारा उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष मदन लाल निगम, सदस्य सुनीता मिश्र, सदस्य प्रतिमा सिंह ने रिकवरी के मुकदमे की सुनवाई की। उन्होंने आदेश दिया कि बीमा कंपनी 33 साल का 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वादी को भुगतान करे। इसके तहत ग्राहक को बीमा कंपनी ने 40500 रुपए के बजाय छह लाख रुपए दिए गए।

-लेखक कानूनी मामलों के जानकार हैं

आखिर, मैक्रां ने ऐसा क्या कहा जो भारत के बच्चों के लिए भी फिट बैठता है...?

बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बंदिशों के पक्ष में आए कई देश

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमेनुएल मैक्रां ने नई दिल्ली में इंडिया- एआई इंपैक्ट समिट में अपने की नोट भाषण में भारत से आग्रह किया कि वह बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करे। अपने भाषण में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि जी-7 के अध्यक्ष के रूप में फ्रांस की कोशिश है कि वह एआई और डिजिटल दुनिया के गलत असर से बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि, इसी वजह से वे फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सेशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया आरंभ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि, स्पेन समेत यूरोप के कई दूसरे देश भी इस तरह के कदम उठाने जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे भी उस क्लब में शामिल होने पर विचार करें।

आपको बता दें कि, ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस दिशा में कदम उठाते हुए इस उम्र तक के बच्चों के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैप के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के इस कदम के बाद उम्मीद की जा रही है कि दुनिया के तमाम दूसरे देश इस तरह के कदम उठाने की पहल करेंगे।

भारत का रुख

हालांकि भारत ने अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की है लेकिन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिया है कि केंद्र सरकार ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए उम्र आधारित प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। अभी तक भारत में आंध्र प्रदेश और गोवा दो राज्य ऐसे हैं जिन्होंने संकेत दिया है कि वे सोशल मीडिया पर उम्र आधारित बंदिशें लगाने जा रहे हैं।

पिछले महीने, 2025- 26 के लिए जारी इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि, सरकार बच्चों को लक्षित डिजिटल विज्ञापनों पर उम्र आधारित प्रतिबंध लगाने के नियमों को कार्यान्वित करे।

भारत सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाएगी यह तो भविष्य में पता चलेगा लेकिन फिलहाल, सवाल यह उठता है कि ऐसे कौन से सोशल मीडिया मंच हैं जिन पर अडल्ट कंटेट है और जिनके इस्तेमाल से बच्चों को बचाना है और उनकी निगरानी जरूरी है।

अल्डट कंटेंट की उपलब्धता

अडल्ट और अश्लील सामग्री अब केवल अलग-अलग वेबसाइटों तक सीमित नहीं रह गई है। यह कई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर भी आसानी से मिल रही है, जिन्हें आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। बच्चों की पहुंच जिन जगहों तक सबसे ज्यादा है, वहीं यह कंटेंट अलग-अलग रूपों में मौजूद है।

सोशल मीडिया मंच

रील्स, शॉर्ट्स और स्टोरीज़ के जरिए अश्लील इशारों, डांस या भड़काऊ विज़ुअल्स वाला कंटेंट तेजी से परोसा जा रहा है। एल्गोरिदम बार-बार ऐसे विडियो का सुझाव देता है, जिससे बच्चा अनजाने में इसी तरह के कंटेंट की ओर खिंचता चला जाता है।

विडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म

फिल्मों और वेबसीरीज़ के लिए उम्र आधारित नियम तो हैं, लेकिन कई बार ट्रेलर, क्लिप्स और सीन बिना किसी साफ चेतावनी के सामने आ जाते हैं, जिन्हें बच्चे भी आसानी से देख लेते हैं।

गेमिंग प्लेटफॉर्म और इन-गेम चैट

ऑनलाइन गेम्स के भीतर चैट फीचर, कस्टम अवतार और थर्ड-पार्टी लिंक के जरिए अश्लील भाषा और कंटेंट तक पहुंच बन जाती है, जिस पर पैरेंट्स का ध्यान कम ही जाता है।

बच्चों इसे मत देखो कहना ही काफी नहीं

पैरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि बच्चों को सख्त शब्दों में मना कर देने से समस्या हो जाएगी, लेकिन आज के डिजिटल दौर में यह तरीका न तो कारगर है और न ही प्रैक्टिकल। मोबाइल और इंटरनेट बच्चों की पढ़ाई, दोस्ती और मनोरंजन का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में सिर्फ फोन मत देखो या ऐसा कंटेंट मत देखो, कहना बच्चों को रोकने के बजाय उन्हें छुपकर देखने की ओर धकेल सकता है। तकनीक के इस्तेमाल को पूरी तरह रोकने के बजाय उसे सुरक्षित और सीमित करने पर फोकस करना ज्यादा असरदार होता है।

निगरानी के लिए उपलब्ध ऐप्स

वॉचर पैरेंटल कंट्रोल (Watcher-Parental Control)

यह मोबाइल ऐप पैरेंट्स बच्चे के स्मार्टफोन को रिमोटली मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लाइव स्क्रीन शेयरिंग, फोटो और विडियो गैलरी तक एक्सेस, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग, कॉल रिकॉर्डिंग और फाइल ट्रांसफर जैसे फीचर्स से उनके मोबाइल की पूरी निगरानी कर सकते हैं।

ScrinTrim, Break Screen-Time

अगर बच्चा छोटा है और वह पैरेंट्स का ही स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है तो यह ऐप उसे ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल से रोकेगा।

FlashGet Kids

इस ऐप से बच्चे के फोन की रीयल-टाइम निगरानी के साथ मोबाइल इस्तेमाल को सीमित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह कहां है, उसके फोन के कैमरे के सामने क्या है, उसके आस-पास क्या आवाजें आ रही हैं, ये सब आप इस ऐप से पता लगा सकते हैं।

Screen Time

आईफोन यूज़र बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखना चाहते हैं तो उसमें Screen Time मददगार साबित होगा। यह Apple का फीचर है, न कि कोई अलग से ऐप। एंड्रॉइड में इसी तरह का फीचर Digital Wellbeing नाम से आता है। इसमें हर दिन की टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं।

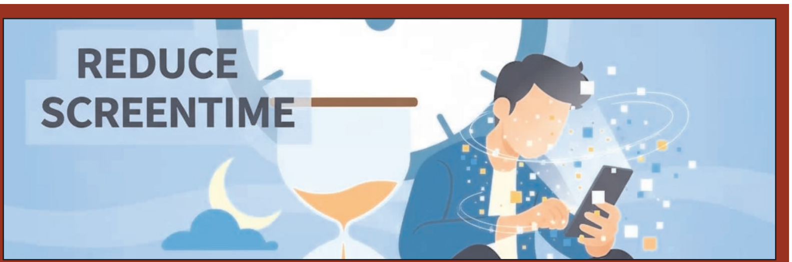

Google Family Link

अगर बच्चे की उम्र 13 साल से कम है और वह अलग मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है तो उसकी निगरानी के लिए यह मददगार साबित होगा।

इसमें बच्चे का Gmail अकाउंट बनाना होता है, जिसके साथ पैरेंट के Gmail अकाउंट की भी जानकारी डालनी होती है। बच्चा कौन-कौन से ऐप यूज़ करे, साथ ही रात में कितने बजे के बाद उसका फोन लॉक हो जाए, यह सब इस ऐप के जरिए तय कर सकते हैं।

सेटिंग बदल कर, कर सकते हैं कंट्रोल

यूट्यूब

YouTube पर बच्चे काफी समय बिताते हैं। मोबाइल पर इस की सेटिंग्स में जाकर General के ऑप्शन से Restricted Mode ऑन कर सकते हैं। इससे अडल्ट कॉन्टेंट उनके सामने नहीं आएगा और ऐसे विडियो अपने-आप फ़िल्टर हो जाएंगे।

इंस्टाग्राम

Instagram पर बच्चों के लिए सेफ्टी सेटिंग्स करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहां रील्स और एक्सप्लोर सेक्शन के जरिए खराब कंटेंट तेजी से सामने आ सकता है। पैरेंट्स सबसे पहले बच्चे के अकाउंट को Private Account में बदलें, ताकि अनजान लोग फॉलो न कर सकें। इसके बाद ऐप की Settings and activity में जाकर Content preferences के ऑप्शन पर जाएं। यहां Sensitive content के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे Less पर सेट कर दें।

चैट जीपीटी

ChatGPT जैसे AI टूल्स पढ़ाई, सवाल-जवाब और सामान्य बातों की जानकारी के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन बिना निगरानी के इस्तेमाल पर जोखिम भी हो सकता है। ChatGPT में पैरेंट्स बच्चों को फैमिली अकाउंट से जोड़कर उनके इस्तेमाल पर नजर रख सकते हैं।

गूगल जैमिनी

सबसे पहले बच्चे का Google अकाउंट Family Link से मैनेज करें, ताकि उम्र के हिसाब से कटेंट और फीचर्स पर कंट्रोल रहे। इसके लिए प्ले स्टोर के जरिए फैमिली लिंक ऐप को डाउनलोड करें। बच्चे का Gmail अकाउंट इस ऐप से जोड़ें।

नेट नैनी (Net Nanny)

यह एक पैरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर और ऐप है जो पैरेंट्स को अपने बच्चों की ऑनलाइन ऐक्टिविटी पर ज्यादा कंट्रोल देता है। इसकी मदद से पैरेंट्स बच्चों को इंटरनेट पर मौजूद अश्लील, हिंसक और नुकसानदायक कॉन्टेंट से बचा सकते हैं। यह रीयल-टाइम वेब फिल्टरिंग के जरिए अडल्ट वेबसाइट्स को ब्लॉक करता है, स्क्रीन टाइम तय करने देता है और यह भी दिखाता है कि बच्चा किन ऐप और साइट्स का इस्तेमाल कर रहा है।

कैनोपी Canopy

यह एक स्मार्ट पैरेंट्ल कंट्रोल ऐप और डिजिटल सेफ्टी टूल है। यह ऐप रियल-टाइम में AI-पावर्ड फिल्टरिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे वेबसाइट्स, विडियो और इमेज को पहले ही स्कैन कर बहुत जल्दी किसी भी अश्लील कॉन्टेंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। यह सिर्फ साइट ब्लॉक ही नहीं करता बल्कि कई बार सुझाए जा रहे अश्लील इमेज/विडियो को भी पहचानकर रोक देता है, ताकि बच्चा गलती से भी उसे न देख सके।

अभिभावकों के लिए सबसे जरूरी बात

अभिभावकों, ऐप्स और मॉनमिटरिंग तो अपनी जगह है लेकिन सबसे जरूरी है अपने बच्चो के साथ समय व्यतीत करना। बच्चे मोबाइल की तरफ कब भागते हैं जब वे न तो खेलने जाते हैं या मां-बाप अपने-अपने मोबाइल पर व्यस्त होते हैं। ऐसे में मां-बाप किस मुंह से बच्चों को मोबाइल से परहेज करने को कह सकते हैं। इसलिए कृपया, बच्चों को अडल्ट कंटेंट से तो बचाइए ही साथ ही वे स्वस्थ और जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकें इसके लिए सक्रिय भी बनिए।

अजय कुमार खुशबू

यूं ही नहीं है, बागपत की सिसाना पंचायत दूसरों के लिए एक आदर्श...

पंचायत में बुनियादी सुविधाओं पर विशेष फोकस, महिला विकास एवं रोजगार के सवालों पर विशेष ध्यान

ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका के इस अंक में हम आपका परिचय उत्तर प्रदेश की आदर्श ग्राम पंचायत सिसाना से कराएंगे। इस पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सफाई जैसे क्षेत्रों में अनुकरणीय काम किया है।

सिसाना का परिचय

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य में ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यह सबसे निचली इकाई न केवल स्थानीय शासन को मजबूत करती है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार और सामाजिक समरसता जैसे क्षेत्रों में ठोस बदलाव का माध्यम भी बनती है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के जिला बागपत की ग्राम पंचायत सिसाना के बारे में एक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे विभिन्न विकासात्मक पहलों, सामुदायिक भागीदारी और पारदर्शी प्रशासन के कारण एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में देखा जाता है।

भौगोलिक एवं सामाजिक परिचय

ग्राम पंचायत सिसाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान है और गंगा–यमुना दोआब के उपजाऊ मैदानों का हिस्सा है। गांव की कुल जनसंख्या लगभग 6–7 हजार के आसपास मानी जाती है, जिसमें विभिन्न सामाजिक वर्ग, किसान, श्रमिक, व्यापारी और सेवा क्षेत्र से जुड़े परिवार शामिल हैं।

सिसाना की सामाजिक संरचना विविध होने के बावजूद आपसी सहयोग और सामुदायिक समरसता भावना इसकी पहचान रही है। पंचायत ने सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए सामूहिक बैठकों, ग्राम सभाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नियमित रूप से प्रोत्साहित किया।

पंचायत प्रशासन और नेतृत्व

सिसाना ग्राम पंचायत की सफलता में सशक्त नेतृत्व और सक्रिय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और वार्ड सदस्यों ने मिलकर टीम-आधारित शासन का मॉडल अपनाया।

- नियमित ग्राम सभा की बैठकें
- विकास योजनाओं की सार्वजनिक जानकारी
- सोशल ऑडिट और सूचना पट्ट पर सार्वजनिक सूचनाएं

ग्राम पंचायत सिसाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान है और गंगा–यमुना दोआब के उपजाऊ मैदानों का हिस्सा है। गांव की कुल जनसंख्या लगभग 6–7 हजार के आसपास मानी जाती है, जिसमें विभिन्न सामाजिक वर्ग, किसान, श्रमिक, व्यापारी और सेवा क्षेत्र से जुड़े परिवार शामिल हैं।

इन उपायों से पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता और जनता का विश्वास मजबूत हुआ।

स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सिसाना पंचायत ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

स्वच्छता पहल

- गांव को खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाने का प्रयास
- घर-घर शौचालय निर्माण
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

पर्यावरण संरक्षण

- वृक्षारोपण अभियान
- तालाबों और जलस्रोतों का पुनर्जीवन
- प्लास्टिक उपयोग के प्रति जागरूकता

इन पहलों से गांव का पर्यावरणीय संतुलन बेहतर हुआ और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई।

शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय पहल

ग्राम पंचायत सिसाना ने शिक्षा को दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा।

- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प
- स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा की शुरुआत
- बालिका शिक्षा पर विशेष जोर

पंचायत द्वारा शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन समिति के बीच समन्वय स्थापित किया गया, जिससे विद्यालयों में नामांकन और उपस्थिति दोनों में सुधार हुआ।

स्वास्थ्य और पोषण

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए पंचायत ने निम्नलिखित कदम उठाए :

- नियमित स्वास्थ्य शिविर
- टीकाकरण अभियान
- आंगनवाड़ी केंद्रों का सशक्तिकरण

विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, जिससे कुपोषण और एनीमिया जैसे मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई।

कृषि और आजीविका विकास

कृषि, सिसाना की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। पंचायत ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई नवाचार किए।

- उन्नत बीज और जैविक खेती का प्रोत्साहन
- किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम
- स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता

महिलाओं को डेयरी, सिलाई-कढ़ाई और लघु उद्योगों से जोड़ा गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई।

बुनियादी ढांचा विकास

ग्राम पंचायत ने बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया।

- पक्की सड़कों का निर्माण
- स्ट्रीट लाइट और सौर ऊर्जा
- स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता

इन सुविधाओं से गांव की जीवन गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार हुआ।

डिजिटल और ई-गवर्नेंस

डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सिसाना पंचायत ने तकनीक को अपनाया।

- ऑनलाइन प्रमाण पत्र सेवाएं
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा
- पंचायत रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण

इससे प्रशासनिक कार्यों में समय और संसाधनों की बचत हुई।

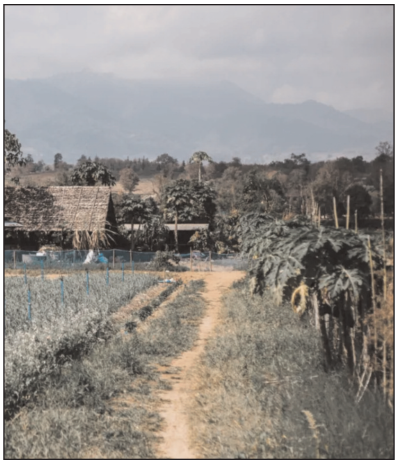

ग्राम पंचायत सिसाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान है और गंगा–यमुना दोआब के उपजाऊ मैदानों का हिस्सा है। गांव की कुल जनसंख्या लगभग 6–7 हजार के आसपास मानी जाती है, जिसमें विभिन्न सामाजिक वर्ग, किसान, श्रमिक, व्यापारी और सेवा क्षेत्र से जुड़े परिवार शामिल हैं। सिसाना की सामाजिक संरचना विविध होने के बावजूद आपसी सहयोग और सामुदायिक समरसता भावना इसकी पहचान रही है। पंचायत ने सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए सामूहिक बैठकों, ग्राम सभाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नियमित रूप से प्रोत्साहित किया।

सामाजिक सुरक्षा और समावेशन

पंचायत ने समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया है।

- वृद्धावस्था और विधवा पेंशन
- दिव्यांग सहायता योजनाएं
- आवास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

सभी लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की गई, जिससे पारदर्शिता बनी रही।

महिला सशक्तिकरण

महिलाओं की भागीदारी सिसाना पंचायत की एक प्रमुख विशेषता है।

- महिला स्वयं सहायता समूह
- ग्राम स्तरीय महिला समितियां
- बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य पर जागरूकता

इन प्रयासों से महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनीं।

चुनौतियां और समाधान

हालांकि सिसाना पंचायत ने उल्लेखनीय प्रगति की, फिर भी कुछ चुनौतियां बनी रहीं -

- सीमित वित्तीय संसाधन
- युवा रोजगार के अवसर
- शहरीकरण का दबाव

पंचायत ने जिला प्रशासन और राज्य योजनाओं के समन्वय से इन चुनौतियों का समाधान खोजने का प्रयास किया।

अन्य पंचायतों के लिए सीख

सिसाना ग्राम पंचायत का मॉडल अन्य ग्राम पंचायतों के लिए प्रेरणादायी है।

- सामुदायिक भागीदारी
- पारदर्शी प्रशासन
- दीर्घकालिक विकास दृष्टि

सिसाना ग्राम पंचायत का मॉडल यह सिद्ध करता है कि यदि नेतृत्व ईमानदार हो, जनता सहभागी हो और योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से किया जाए, तो सीमित संसाधनों के बावजूद भी ग्रामीण विकास का मजबूत मॉडल खड़ा किया जा सकता है। यह पंचायत उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में अनुकरणीय हो सकती है।

-लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

मनोज दीक्षित

किसानों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा बजट...?

सरकार का जोर दूरगामी रणनीति पर

किसानों की फौरी मांगों का समाधान जरूरी

साल 2026 के आम बजट के बारे में दावा किया गया है कि यह किसानों और ग्रामीण भारत को केंद्र में रखकर प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को 'कृषि और ग्रामीण विकास' का बजट बताया है। लेकिन, सवाल यह है कि, वित्त मंत्री के इस दावे में कितना दम है ? क्या ये घोषणाएँ किसानों की ज़िंदगी में वास्तविक बदलाव ला पाएंगी, या ये भी पिछले बजटों की तरह केवल कागज़ी वादों तक सीमित रह जाएंगी ?

वादों की चमक

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.63 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। उच्च मूल्य वाली खेती—नारियल, काजू और चंदन—को बढ़ावा देने की योजना है। पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान हुआ है। किसानों और ग्रामीण युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए शॉर्ट-टर्म कोर्स और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

किसान उत्पादक

संगठनों (FPOs) को मज़बूत करने की बात कही गई है। कागज़ पर यह सब सुनने में आकर्षक लगता है। यह तस्वीर दिखाती है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गंभीर है।

फायदे

- **आय में विविधता:** उच्च मूल्य वाली फसलों से किसानों को नए बाज़ार मिलेंगे और पारंपरिक फसलों पर निर्भरता कम होगी।
- **पशुपालन और मत्स्य पालन:** अतिरिक्त आय का स्रोत बनेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी।
- **शिक्षा और प्रशिक्षण:** आधुनिक तकनीक से जुड़कर उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है।
- **रोजगार सृजन:** ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्यम खड़े होंगे।
- **FPOs की ताकत:** सामूहिक संगठन किसानों को बेहतर दाम दिला सकते हैं।

नुकसान और चुनौतियां

- **MSP पर चुप्पी:** न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यह किसानों की सबसे बड़ी चिंता है।
- **क्रियान्वयन की कमी:** पिछले बजटों की तरह योजनाएं ज़मीन पर उतरेंगी या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है।
- **ग्रामीण ढांचे की कमी:** सप्लाई चेन, कोल्ड स्टोरेज और मार्केटिंग नेटवर्क की कमी योजनाओं को कमजोर कर सकती है।
- **शिक्षा और प्रशिक्षण का असर:** इंटरनेट और तकनीक की कमी वाले इलाकों में इसका लाभ सीमित रह सकता है।
- **कर्ज का बोझ:** कर्ज माफी या ब्याज राहत जैसी कोई घोषणा नहीं हुई। छोटे किसान दबाव में रहेंगे।

इस बजट को केवल घोषणाओं की सूची मानना आसान है, लेकिन असली सवाल यह है कि किसानों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के

बजट किसानों को अवसर देता है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। अगर सरकार योजनाओं को ज़मीन पर उतारने में सफल रही तो यह ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम साबित होगा। लेकिन अगर घोषणाएं केवल भाषणों तक सीमित रह गईं, तो किसानों की आय दोगुनी करने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने का सपना तभी पूरा होगा जब योजनाएं केवल भाषणों तक सीमित न रहकर ज़मीन पर उतरें। अन्यथा यह बजट भी उन वादों की लंबी सूची में शामिल हो जाएगा जो किसानों की ज़िंदगी बदलने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में अधूरी उम्मीदें छोड़ जाते हैं।

लिए क्या सरकार ने उनकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश की है।

- किसान की समस्या केवल आय नहीं है, बल्कि उसका सामाजिक और मानसिक दबाव भी है। जब किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, जब वह कर्ज के बोझ तले दबा रहता है, तब कोई भी सब्सिडी या प्रशिक्षण उसके दर्द को कम नहीं कर सकता।
- कृषि को केवल उत्पादन और आय के नजरिए से देखना अधूरा है। यह किसानों की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। बजट में इन पहलुओं पर कोई ठोस योजना नहीं दिखती।
- बजट 2026 किसानों के लिए दिशा तो तय करता है—आय बढ़ाने, रोजगार सृजन और उच्च मूल्य वाली खेती पर जोर। लेकिन मंज़िल तक पहुंचने के लिए ठोस और पारदर्शी क्रियान्वयन की ज़रूरत है।
- MSP और कर्ज राहत जैसे मुद्दों पर चुप्पी किसानों की उम्मीदों को तोड़ती है।

यह बजट किसानों को अवसर देता है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। अगर सरकार योजनाओं को ज़मीन पर उतारने में सफल रही तो यह ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम साबित होगा। लेकिन अगर घोषणाएं केवल भाषणों तक सीमित रह गईं, तो किसानों की आय दोगुनी करने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने का सपना तभी पूरा होगा जब योजनाएं केवल भाषणों तक सीमित न रहकर ज़मीन पर उतरें। अन्यथा यह बजट भी उन वादों की लंबी सूची में शामिल हो जाएगा जो किसानों की ज़िंदगी बदलने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में अधूरी उम्मीदें छोड़ जाते हैं।

किसानों के लिए प्रमुख घोषणाएं

- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.63 लाख करोड़ का प्रावधान।
- उच्च मूल्य वाली खेती (नारियल, काजू, चंदन) को बढ़ावा देने की योजना।
- पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम।

किसान सेंटर

सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए कई दूरगामी योजनाओं का खाका तो खींचा है लेकिन उन योजनाओं को किसानों की फौरी जरूरतों के साथ जोड़ना भी एक बड़ी चुनौती है। MSP और कर्ज राहत जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाकर एवं प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे को मज़बूत करके, सरकार किसानों की उम्मीदों और अपनी घोषणाओं के बीच की दूरी कम कर सकती है।

- किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए शॉर्ट-टर्म कोर्स और प्रशिक्षण।
- किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को प्रोत्साहन।
- ग्रामीण रोजगार और आय वृद्धि पर विशेष ध्यान।

क्या कहना है किसानों का?

सरकार ने बजट 2026 को किसानों और ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक बताते हुए पेश किया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सवाल यही है कि क्या यह बजट किसानों की असली समस्याओं को हल कर पाएगा। घोषणाएं आकर्षक हैं, लेकिन ज़मीन पर रहने वाले किसान क्या सोचते हैं, यही असली कसौटी है।

- उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के रहने वाले रामस्वरूप यादव, छोटे किसान का कहना है कि, हमारी सबसे बड़ी समस्या फसल का दाम है। MSP की गारंटी नहीं मिली तो बाकी सब योजनाएं हमारे लिए दूर की बात हैं। हमें अपनी फसल का सही मूल्य चाहिए, ताकि कर्ज से बाहर निकल सकें।
- बिहार के सीमांत इलाके की सावित्री देवी का कहना है कि, सरकार कहती है कि पशुपालन और मत्स्य पालन से आय बढ़ेगी। लेकिन हमारे गांव में न तो कोल्ड स्टोरेज है, न ही बाज़ार तक पहुँच। अगर ढांचा ही नहीं होगा तो हम इन योजनाओं का लाभ कैसे ले सकेंगे
- पंजाब के किसान, गुरमेल सिंह के अनुसार, FPOs की बात अच्छी है। अगर किसान मिलकर काम करेंगे तो ताकत बढ़ेगी। लेकिन सरकार को यह भी देखना होगा कि छोटे किसानों को संगठन तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण और भरोसा मिलना चाहिए।
- मध्य प्रदेश के युवा किसान शंकरलाल के अनुसार, शॉर्ट-टर्म कोर्स और तकनीक की बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन हमारे गांव में इंटरनेट ही नहीं है। अगर तकनीक तक पहुंच नहीं होगी तो यह योजना केवल शहरों तक सीमित रह जाएगी।

किसानों की प्रतिक्रिया जाहिर करती है कि, उनकी मूलभूत चिंताएं, MSP, कर्ज राहत और बुनियादी ढांचे का विकास जैसे मसले हैं और इन मसलों को बजट में अपेक्षाकृत तरजीह नहीं मिल पाई है। सरकार ने दीर्घकालिक योजनाओं पर जोर दिया है, लेकिन किसानों की तात्कालिक समस्याओं का समाधान नहीं किया।

यह बजट किसानों को अवसर देता है, लेकिन उनकी ज़मीन से जुड़ी मांगों को अधूरा छोड़ देता है। अगर सरकार ने क्रियान्वयन में गंभीरता दिखाई और बुनियादी ढांचे को मज़बूत किया तो यह ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम साबित होगा। लेकिन अगर घोषणाएं केवल भाषणों तक सीमित रह गईं, तो किसानों की आवाज़ फिर से अधूरी उम्मीदों में बदल जाएगी।

कहा जा सकता है कि सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए कई दूरगामी योजनाओं का खाका तो खींचा है लेकिन उन योजनाओं को किसानों की फौरी जरूरतों के साथ जोड़ना भी एक बड़ी चुनौती है। MSP और कर्ज राहत जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाकर एवं प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे को मज़बूत करके, सरकार किसानों की उम्मीदों और अपनी घोषणाओं के बीच की दूरी कम कर सकती है।

क्या किया जा सकता है ?

- MSP को कानूनी गारंटी देकर किसानों को फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाए।
- कर्ज राहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए ब्याज माफी या आंशिक कर्ज माफी की योजना लागू की जाए।
- ग्रामीण ढांचा कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और सप्लाई चेन को मज़बूत किया जाए ताकि फसल खराबन हो और बाज़ार तक पहुंचे।
- कृषि बीमा बीमा योजनाओं को सरल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि किसानों को समय पर मुआवज़ा मिल सके।
- तकनीकी प्रशिक्षण गांव-गांव में डिजिटल सेंटर और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएं, ताकि किसान आधुनिक तकनीक से जुड़ सकें।
- सीधी नकद सहायता छोटे किसानों को सीधे नकद सहायता दी जाए, ताकि वे खेती में निवेश कर सकें।
- पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्रों में सप्लाई चेन और मार्केटिंग नेटवर्क विकसित कर किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर दिया जाए।
- किसान उत्पादक संगठनों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर उन्हें बाज़ार तक सीधी पहुंच दिलाई जाए।
- सामाजिक सुरक्षा किसानों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और पेंशन योजनाएं लागू की जाएं।

-लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

FEEDBACK — M9711011045@GMAIL.COM

जीवन ज्योति

इन खतरों से मुंह फेरना पड़ जाएगा भारी...!

विकास के साथ चुनौतियों का पिटारा भी, इंसानी गतिविधियों का पर्यावरण के साथ संतुलन जरूरी

भारत आज विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बुनियादी ढांचे का विस्तार, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और ऊर्जा की बढ़ती मांग ने विकास की नई इबारत लिखी है। किंतु इसी विकास के साथ पर्यावरणीय संकट भी गहराया है। वायु प्रदूषण, जल संकट, भूमि क्षरण, जैव-विविधता का ह्रास, जलवायु परिवर्तन और कचरा प्रबंधन जैसी चुनौतियां गंभीर रूप ले चुकी हैं। हाल के वर्षों में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थानों, जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs), भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), नीति आयोग, TERI तथा अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित अध्ययनों ने इन समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ-साथ ठोस समाधान भी प्रस्तुत किए हैं। यह आलेख भारत के संदर्भ में हालिया शोधों के प्रमुख निष्कर्षों और उनसे सुझाए गए समाधान की दिशा में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है।

वायु प्रदूषण: शोध और नीतिगत समाधान

हालिया शोध के निष्कर्ष

भारत के महानगरों, दिल्ली, लखनऊ, पटना, कानपुर, मुंबई आदि में PM2.5 और PM10 कणों का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों से कई गुना अधिक पाया गया है। IIT कानपुर और IIT दिल्ली के अध्ययनों ने स्पष्ट किया है कि शहरी वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं :

- वाहन उत्सर्जन
- निर्माण गतिविधियां
- थर्मल पावर प्लांट
- ईंट भट्टे
- पराली जलाना
- घरेलू बायोमास ईंधन

हाल के शोधों ने यह भी दिखाया है कि केवल एक कारक को नियंत्रित करने से प्रदूषण में सीमित कमी आती है; बहु-स्रोत रणनीति आवश्यक है।

समाधान की राह

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार : नीति आयोग और ऊर्जा मंत्रालय के अध्ययन बताते हैं कि यदि 2030 तक 30-40 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएं तो शहरी प्रदूषण में 15-20 फीसदी तक कमी संभव है।

- **स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम:** कोयला आधारित ऊर्जा पर निर्भरता कम कर सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा।
- **पराली प्रबंधन के वैज्ञानिक उपाय:** बायो-सीएनजी, कम्पोस्टिंग और हैप्पी सीडर मशीन का उपयोग।
- **शहरी हरित पट्टियां (Urban Green Buffers):** IISc के शोध में पाया गया कि हरित क्षेत्रों की वृद्धि से स्थानीय तापमान और प्रदूषण स्तर कम होता है।
- **रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और जनभागीदारी:** डेटा आधारित नीति निर्माण करना।

जल संकट और जलवायु परिवर्तन

जल संकट पर शोध

नीति आयोग की कंपोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि भारत के 21 प्रमुख शहर गंभीर भूजल संकट का सामना कर सकते हैं। IIT गांधीनगर और IISc के शोध बताते हैं कि:

- वर्षा का पैटर्न अनिश्चित हो रहा है।
- अत्यधिक वर्षा और लंबे सूखे की घटनाएं बढ़ रही हैं।
- हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन को प्रभावित कर रहा है।

समाधान की राह

वर्षा जल संचयन का अनिवार्य क्रियान्वयन

- **जल पुनर्चक्रण (Wastewater Recycling):** चेन्नई और इंदौर जैसे

शोध

शहर उदाहरण बने हैं।

- **सूक्ष्म सिंचाई (Drip & Sprinkler):** कृषि में 30-50% जल बचत संभव।
- **जलवायु अनुकूल कृषि:** सूखा-रोधी बीज और फसल विविधीकरण।
- **नदी पुनर्जीवन मॉडल:** जैसे नमामि गंगे मिशन के तहत अपशिष्ट प्रबंधन।

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र

शोध के निष्कर्ष

भारत विश्व की 8 प्रतिशत जैव विविधता का घर है, लेकिन IUCN और भारतीय वन्यजीव संस्थान के शोध के अनुसार कई प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। शहरी विस्तार, खनन, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण हैं।

हालिया अध्ययन बताते हैं कि मैंग्रोव और वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

समाधान की राह

- समुदाय आधारित संरक्षण (Community-led Conservation)
- वनरोपण नहीं, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन (Ecological Restoration)
  ईको-टूरिज्म का नियंत्रित विकास
- वन्यजीव कॉरिडोर की सुरक्षा

ठोस अपशिष्ट और प्लास्टिक प्रदूषण

शोध के निष्कर्ष

CPCB और NEERI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें प्लास्टिक का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है।

IIT मद्रास के अध्ययन ने माइक्रोप्लास्टिक के समुद्री जीवन पर दुष्प्रभाव को रेखांकित किया है।

समाधान का रास्ता

- स्रोत पर कचरा पृथक्करण अनिवार्य
- सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर सख्त प्रतिबंध
- सर्कुलर इकॉनमी मॉडल
- कचरे से ऊर्जा (Waste-to-Energy) परियोजनाएँ

जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण

शोध के निष्कर्ष

IPCC की रिपोर्ट और भारतीय मौसम विभाग के अध्ययन बताते हैं कि भारत में जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण के कई तरह बदलाव देखने के मिल रहे हैं।

- हीटवेव की घटनाएं बढ़ रही हैं।
- समुद्री स्तर में वृद्धि से तटीय शहरों पर खतरा है।
- चरम मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं।

समाधान

नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश – भारत ने 500 GW नवीकरणीय क्षमता का लक्ष्य रखा है।

- ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
- कार्बन टैक्स और कार्बन क्रेडिट तंत्र
- क्लाइमेट-रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर

शहरीकरण और हीट आइलैंड प्रभाव

IISc और TERI के शोध के अनुसार महानगरों में Urban Heat Island प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे तापमान ग्रामीण क्षेत्रों से 3-5 डिग्री अधिक हो सकता है।

समाधान का रास्ता

- ग्रीन रूफ और कूल रूफ तकनीक
- शहरी वृक्षारोपण
- जल निकायों का संरक्षण
- ऊर्जा दक्ष भवन निर्माण

कृषि और पर्यावरणीय स्थिरता

हालिया कृषि अनुसंधान (ICAR) दर्शाते हैं कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरता घट रही है।

समाधान का रास्ता

- जैविक और प्राकृतिक खेती
- फसल चक्र (Crop Rotation)
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रभावी क्रियान्वयन
- कार्बन-स्मार्ट कृषि तकनीक

तकनीकी नवाचार और डिजिटल समाधान

भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में सक्रिय है और कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे,

- AI आधारित प्रदूषण पूर्वानुमान
- ड्रोन से वृक्षारोपण
- ब्लॉकचेन आधारित कार्बन क्रेडिट
- स्मार्ट ग्रिड

नीति, शासन और जनभागीदारी

हालिया शोध यह भी दर्शाते हैं कि केवल तकनीकी समाधान पर्याप्त नहीं हैं; सुशासन और जनभागीदारी अनिवार्य है।

प्रमुख कदम

- स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार
- पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में सशक्त बनाना
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) का हरित उपयोग

पारदर्शी पर्यावरणीय आकलन प्रक्रिया

भारत के सामने पर्यावरणीय चुनौतियां गंभीर अवश्य हैं, किंतु हालिया शोध यह आशा भी जगाते हैं कि यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नीतिगत इच्छाशक्ति और जनसहभागिता का समन्वय हो तो समाधान संभव है। विकास बनाम पर्यावरण की बहस अब पुरानी हो चुकी है; आज आवश्यकता है विकास और पर्यावरण के संतुलित मॉडल की।

-लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

किसान भाइयों, लाखों की कमाई का नुस्खा

फरवरी का महीना सब्जियों की बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है क्योंकि इस दौरान न तो अधिक ठंड होती है और न ही अधिक गर्मी, जिससे फसलें तेजी से बढ़ती हैं। फरवरी में लगाई गई लौकी लंबे समय तक उत्पादन देती है। किसान भाई लौकी के साथ बीच-बीच में कद्दू भी लगा सकते हैं ताकि खेती का खर्च कद्दू से निकल जाए और लौकी का मुनाफा शुद्ध बचत हो। यह बहुत कम लागत वाली फसल है और फरवरी में लगाने पर 60-70 रुपये प्रति किलो तक का भाव दिला सकती है। इसमें अधिक खाद या दवा की जरूरत नहीं पड़ती।

गन्ने की बुवाई में रखें इन बातों का ख्याल

गन्ने की बसंत कालीन बुवाई का काम शुरू हो चुका है, अच्छी पैदावार के लिए सबसे पहले खेत को सही तरीके से तैयार करना चाहिए। बुवाई से पहले खेत की गहरी जुताई करना बहुत जरूरी है गन्ने की फसल में अक्सर 'लाल सड़न" नाम की बीमारी लग जाती है, जिसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। यह बीमारी पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। इससे बचने के लिए बुवाई के समय एक खास सावधानी बरतनी चाहिए। कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि बुवाई से पहले 100 लीटर पानी में ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाएं। अब गन्ने के टुकड़ों को इस घोल में 10 से 15 मिनट तक डुबोकर रखें और उसके बाद ही उनकी बुवाई करें।

कम लागत में कमा सकते हैं लाखों का मुनाफा

तरबूज की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में की जाती है। अन्य फलों की फसलों की तुलना में इस फल को कम समय, कम खाद और कम पानी की आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम की शुरुआत में भारत में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती की जाती है। इस दौरान बाजार में तरबूज के फल की काफी डिमांड रहती है। ऐसे में किसान इसकी खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है।

आलू की ग्रेडिंग से मिलेंगे बढ़िया दाम

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आलू की खुदाई का सीजन चल रहा है। किसानों के लिए असली चुनौती अब शुरू होती है। अक्सर किसान पूरी फसल को एक साथ मंडी ले जाते हैं, जिससे उन्हें वाजिब दाम नहीं मिल पाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल बंपर कमाई का मंत्र 'ग्रेडिंग" में छिपा है। अगर किसान खुदाई के तुरंत बाद आलू की सही छंटाई करें, तो वे अपनी आय में भारी इजाफा कर सकते हैं। यह छोटा सा बदलाव किसानों की मेहनत को मिट्टी के मोल बिकने से बचा सकता है। किसानों को चाहिए कि वे 'A, B और C" ग्रेड में आलू को बांट लें। इसमें कटे-फटे या रोगग्रस्त आलू को हटा दें। अच्छी ग्रेडिंग से फसल की 'शेल्फ लाइफ" बढ़ती है और खरीदार प्रीमियम दाम देने को तैयार रहता है।

गेहूं की फसल में ना करें यह चूक

गेहूं की खेती करने वाले किसानों को अच्छा खासा मुनाफा होता है। कम लागत में अधिक मुनाफा गेहूं की खेती से कमाया जा सकता है। वही गेहूं की फसल में बाली निकलते समय पौधे का भार ऊपर की ओर बढ़ जाता है। इस अवस्था में तेज हवा के दौरान सिंचाई की जाती है, तो फसल जमीन पर गिर सकती है, जिससे फसल उत्पादन में कमी आती है। अगर किसान इस समय सही से देख-रेख कर लें, तो दाने न केवल वजनदार और चमकदार बनते हैं, बल्कि उत्पादन भी बेहतर मिलता है।

चूहों को भगाने के असरदार देसी तरीके

खेती में चूहों की समस्या बहुत गंभीर होती है। अक्सर किसान इन्हें मारने के लिए जहरीली दवाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन यहां कुछ ऐसे जैविक और आसान तरीके बताए गए हैं जिनसे बिना चूहों को मारे आप उन्हें अपने खेत से हमेशा के लिए दूर रख सकते हैं। पहला प्रभावी तरीका चूहों के बिलों में 'धुआं" करना है। आप रूई के फाहों को फिनाइल में भिगोकर चूहों के बिलों के प्रवेश द्वार पर रख सकते हैं, जिससे वे दोबारा उस रास्ते से नहीं आएंगे। तीसरा और सबसे सफल तरीका 'कपूर की टिक्की" का इस्तेमाल करना है। कपूर की एक टिक्की के छोटे टुकड़े करके उन्हें बिलों के पास रख दें। कपूर की गंध इतनी तेज होती है कि चूहे तो क्या, सांप और गोयरा जैसे जहरीले जीव भी खेत के आसपास नजर नहीं आएंगे।

ग्रामीण उपभोक्ता टीम

बीमारी और बिल से मिलेगी आजादी

बुढ़ापे की सबसे बड़ी चिंता होती है बीमारी और बिल। पेंशन नियामक PFRDA एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है, जो आपके रिटायरमेंट को 'बीमारी और बिल' के डर से आजाद कर सकती है। इसे नाम दिया गया है स्वास्थ्य पहल। अब आपका NPS निवेश सिर्फ रिटायरमेंट फंड नहीं, बल्कि एक मेडिकल पेंशन पूल भी बनेगा। PFRDA का कहना है कि अब NPS सिर्फ एक रिटायरमेंट फंड नहीं रहेगा। तीन बड़े फंड मैनेजर, ICICI, Axis और Tata ऐसे उत्पादों पर प्रयोग कर रहे हैं, जो पेंशन को हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जोड़ सकेंगे।

सिर्फ एक बार निवेश, फिर हर महीने 10,000

एलआईसी स्मार्ट पेंशन योजना (LIC Smart Pension Scheme) के तहत एकमुश्त वन टाइम निवेश के बाद पेंशन के रूप में कमाई शुरू हो जाती है और जीवनभर मिलती रहती है। LIC का स्मार्ट पेंशन प्लान खासतौर पर ऐसे निवेशकों के लिए बेस्ट माना जाता है, जो शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर गारंटीड और नियमित इनकम के लिए निवेश करने का प्लान करते हैं। यह Non-Linked और Non-Participating LIC Plan है, मतलब इसमें बाजार से जुड़ा रिस्क जीरो (Zero Risk Pension Plan) है। LIC Smart Pension Scheme में न्यूनतम एन्युटी खरीद 1 लाख तय की गई है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई लिमिट हीं है, यानी आप जितना चाहे, इसमें निवेश कर सकते हैं।

PM Kisan की किस्त से जुड़ी जरूरी खबर

पीएम किसान की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियो के लिए जरूरी खबर है। 22वीं किस्त के जारी करने को लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई डेट तय नहीं हुआ है। यह 31 मार्च से पहले जारी हो सकती है। पीएम किसान की 22वीं किस्त से पहले वेबसाइट पर कुछ नई सुविधाएं दी गई हैं। जैसे, अगर कोई इन्फार्मेशन मिसिंग है तो उसे अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। अगर अपात्र होने के बावजूद पीएम किसान की किस्त ले रहे हैं तो ऑन लाइन रिफंड करने की सुविधा भी वेबसाइट पर मौजूद है।

पीएफ का अनक्लेम्ड पैसा सीधे खाते में

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और श्रम मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत लाखों निष्क्रिय पीएफ खातों में जमा अनक्लेम्ड पैसा सीधे सब्सक्राइबर्स के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार का यह कदम उन लोगों के लिए राहत की बात है जिन्हें क्लेम करने की झंझट के कारण अपने छोटे-छोटे पीएफ बैलेंस नहीं मिल पाए थे। पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में उन खातों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां 1000 रुपए या उससे कम का बैलेंस है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसे लगभग 7.11 लाख खाते हैं जिनमें कुल 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पड़ी है।

छोटी कारें हो सकती हैं महंगी

छोटी कारें बनाने वाली कंपनियों के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। अगर ईंधन की बचत और प्रदूषण कम करने से जुड़ा CAFE-3 का नया ड्राफ्ट लागू होता है, तो छोटी कारों को बनाना और बेचना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। जानकारों का कहना है कि अगर कार कंपनियां नए नियमों की वजह से छोटी कारें बनाने में कम दिलचस्पी लेंगी, तो इससे उन लोगों को झटका लगेगा जो दोपहिया से कार पर शिफ्ट होना चाहते हैं। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि CAFE-3 लागू होने के बाद नई कारों की लागत करीब 10% तक बढ़ सकती है। कंपनियों को नए नियमों पर खरा उतरने के लिए या तो गाड़ियों में ईंधन बचाने वाली महंगी तकनीक लगानी होगी या फिर भारी जुर्माना भरना होगा।

भारत में 30 लाख घरों में रूफटॉप सोलर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 30 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाने की उपलब्धि को भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा का बड़ा मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम है। प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों को बधाई दी और इसे बचत, स्थिरता और आत्मनिर्भरता से जुड़ा जनआंदोलन बताया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रूफटॉप सोलर अपनाने वाले परिवारों ने न केवल अपने बिजली बिल में कमी लाई है, बल्कि देश को हरित ऊर्जा की ओर आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह योजना ऊर्जा सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और भविष्य के लिए तैयार भारत बनाने की सरकार की सोच का हिस्सा है।

ग्रामीण उपभोक्ता टीम

टोयोटा एबेला ईवी की भारत में एंट्री

2026 टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला ईवी भारत में बड़े पैमाने पर बिकने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में टोयोटा की एंट्री का प्रतीक है और यह मूल रूप से मारुति ई विटारा का ही नया वर्जन है जिसमें कुछ मामूली कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। एक ज्यादा आकर्षक और राउंड शेप के विकल्प के रूप में पेश की गई ईबेला, अपडेटेड बंपर, पिक्सल-स्टाइल एलईडी लाइटिंग और एक साफ-सुथरे ओवरऑल डिजाइन के साथ खुद को अलग पहचान देती है। इसका केबिन ई विटारा के प्रीमियम केबिन से मिलता जुलता है, जिसमें डुअल डिजिटल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीटें, प्रीमियम मैटेरियल्स और एक मजबूत सेफ्टी सिस्टम शामिल है जिसमें सभी आवश्यक सेफ्टी फीचर्स और यहां तक कि लेवल-2 एडीएएस भी शामिल हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 17 लाख रुपए बताई जा रही है।

एमजी मैजेस्टर हुई लॉन्च

एमजी मैजेस्टर भारत में ब्रांड की नई फ्लैगशिप एसयूवी बनने जा रही है, जो फरवरी में लॉन्च की गई है। मैजेस्टर मूल रूप से एमजी ग्लॉस्टर का एक अधिक प्रीमियम और बेहतर वर्जन है और एक अधिक आकर्षक और आक्रामक डिज़ाइन के साथ आएगी, जिसमें एक बड़ी ब्लैक ग्रिल, वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट्स और एक मजबूत लुक शामिल हैं। एमजी मैजेस्टर की एक्स शोरूम कीमत लगभग 45 लाख है। हालांकि, इसके इंटीरियर की डीटेल्स अभी सामने आनी बाकी है, लेकिन स्पाय शॉट्स से पता चलता है कि इसमें बिल्कुल नया डैशबोर्ड लेआउट, बेहतर अपहोल्स्ट्री और छह और सात सीटों वाले कॉन्फ़िगरेशन का विकल्प होगा। प्रमुख फीचर्स में डुअल डिजिटल स्क्रीन, मसाज फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और लेवल-2 एडीएएस शामिल होने की उम्मीद है।

मारुति सुजुकी ई विटारा कार लॉन्च

इस मारुति इलेक्ट्रिक कार के 2025 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद थी, अब आखिरकार फरवरी 2026 में लॉच हो गई है। ई विटारा को ऑटो एक्सपो 2025 में पूरी तरह से डिस्प्ले किया गया था और तब से ईवी ग्राहकों को इसके लॉच का इंतजार था। ईबेला की तरह, इसमें भी कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सात एयरबैग तक और लेवल-2 एडीएएस शामिल हैं। पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन ईबेला एसयूवी के समान ही है, जिसमें दो बैटरी पैक और 5ओओ किलोमीटर से अधिक की दावा की गई रेंज शामिल है। इसकी 17 लाख शोरूम कीमत है।

नए उत्पाद

Sony के नए फ्लैगशिप ईयरबड्स लॉन्च

Sony ने हाल ही में एक टीजर वीडियो शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि वह अपनी "नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ईयरबड्स' को पेश की है। माना जा रहा है कि यह कंपनी के नए फ्लैगशिप ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का नाम WF-1000XM6 नाम दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यह मॉडल 2023 में लॉन्च हुए WF-1000XM5 का सक्सेसर होगा। Sony के टीज़र वीडियो के मुताबिक इसे 'नेक्स्ट जनरेशन' शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि कंपनी इस बार सिर्फ मामूली अपग्रेड नहीं, बल्कि यूज़र एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी में है।

Haier का चार दरवाजे वाला फ्रिज

Haier ने भारतीय बाजार में नया रेफ्रिजरेटर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने लुमियर कलरफुल 4-डोर रेफ्रिजरेटर रेंज लांच किया है। ब्रांड का कहना है कि इस रेफ्रिजेटर रेंज को मॉडर्न होम्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें 520 लीटर की कैपेसिटी मिलती है। रेफ्रिजरेटर कलरफुल स्टील फिनिश के साथ आता है, जो ग्लॉस और मैट ऑप्शन में मिलेगा। इस सीरीज को कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन- पर्ल वॉइट, पिंक और रोसेट वॉइट में लॉच किया है। हायर का नया रेफ्रिजरेटर दमदार फीचर्स के साथ आता है। इसमें स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके लुक को प्रीमियम बनाता है।

देसी कंपनी ने लॉन्च की ईयर बड्स वाली स्मार्ट वॉच

देसी कंज्यूमर टेक ब्रांड Ai+ अपने पोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। स्मार्टफोन्स के बाद अब कंपनी AIoT प्रोडक्ट्स को लॉंच किया है। कंपनी 24 फरवरी को अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को लॉच किय, जिसमें स्मार्टवॉच और ईयरबड्स शामिल हैं। कंपनी NovaPods ऑडियो सीरीज और NovaWatch वियरेबल सीरीज को लॉन्च करने वाली है। ये डिवाइसेस Ai+ के कनेक्टेड इकोसिस्टम के अगले पड़ाव को दिखाते हैं। ब्रांड ने हाल में ही अपने फ्लिप फोन की लॉन्चिंग को भी कन्फर्म किया है, हालांकि, उसकी लॉन्च डेट सामने नहीं आई है। NovaPods ऑडियो सीरीज में कंपनी तीन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगी। ये ईयरबड्स स्पेसिफिक यूजर्स को टार्गेट करेंगे।

Elevate Your Public Image

Amplifying Your Brand's Voice

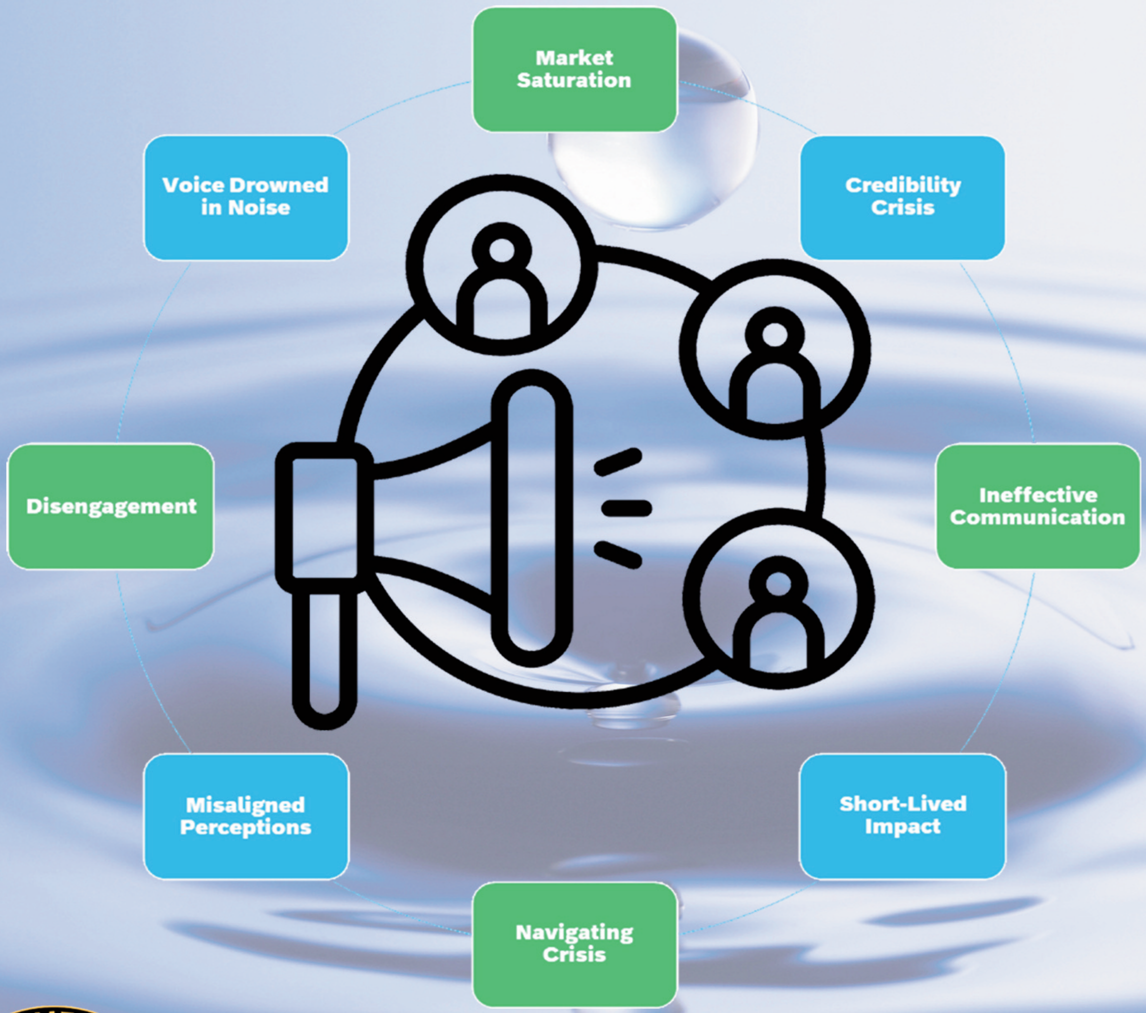

Pratidhwani Media Initiative Pvt. Ltd.

Contact Information

Email: pratidhwanimediainitiative@gmail.com
Website: www.pratidhwanimedia.com
Address: 101, Shahpuri Tower, C-58, Community Center, Janakpuri, New Delhi - 110058

Atulyam

Atulyam Multi State Multi Purpose Cooperative Society

Multi-State Cooperative Society Registered with Registrar of Multi State Cooperative Societies under Multistate Co-operative Societies Act, 2002 (Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, GoI)

CONTACT US

Head Office

101, Shahpuri Tower
C - 58, Community Centre
Janakpuri, New Delhi - 110058
Phone No. - 011-45733115/ 9810085115
Email: atulyam.mscs@gmail.com
www.atulyam.org

Regional Office (Bihar)

Uphrail Chauk,
Ward No. -10, Bypass
Purnea, Bihar –854315